SHRI K. C. PANT: Sir. 1 introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at fortyeight minutes past nne of the clock.

The House reassembled after lunch al half-past two of the Clock, the Vice-Chairman (Shri V. B. Raju) in the Chair.

THE APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1973

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY Oh FINANCE (SHRI K. K. OANESH1: Mr. Vice-Chairman. Sir, 1 beg to move:—

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums trom and out of the Consolidated Fund of India for the Services of the financial year 1973-74, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration".

Sir, this Bill provides for I he withdrawal from the Consolidated Fund of India of ihe amounts required to meet the expenditure charged on the Fund and the grants voted by the Lok Sabha. The figures in (he Bill are brased on the provisions shown in the Demands for Grants and are inclusive of the sums voted 'on account' and provided for in the Appropriation (Vote on Account) Act, 1973 for expenditure during April-May, 1973.

The figures in the Bill represent gross amount of withdrawals to be made from the Consolidated Fund of India and do not take into account the receipts or ac?-justments in reduction of expenditure. The net amounts are shown in the Budget Statement. A reconciliation of the gross anj net figures has been given in Annexure 111 in the Explanatory Memorandum.

As the Hon'ble Members are aware, tne Central budget for 1973-74 makes provision of Rs. 2.844 crores for the Plan comprising Rs. 1,924 crores for outlay on the Central and Centrally sponsored Plan and Rs. 920 crores for Central assistance to wards State and Unoin Territory Plans. In addition, extra Budgetary resources for Central Plan aie estimated to be Rs. 518 crores. The States and Union Territories will provide Rs. 994 crores from their own resources. Thus, taking the Centre, the States and Union Territories together, the total outlay on the Plan in 1973-74 is estimated at Rs. 4,356 crores which reflects a step up of Rs. 345 crores from the estimated outlay in the previous year.

Non-Plan expenditure (Net) includes Rs. 1,600 crores for Defence and Rs. 362 crores for Posts and Telegraphs. Non-Plan Civil expenditure on Revenue Account provides for Rs. 835 crores for interest payments; Rs. 616 crores for payments of States' share of Union Excise Duties, Rs. 388 crores tor grants to State and Union Territoiv Governments. Rs. 397 crores tor developmental expenditure mostly for continuing schemes and maintenance, R«. 130 crores for subsidy to the Food Corporation and Rs. 67 crores for export promotion. Other provisions are spread over a large number of heads representing administrative and tax collection charges, Currency and Mint expenditure and other miscellaneous expenditure. On the Capital side, the nou Plan provisions comprise oi Rs. 586 crores for Loans and Advances io Sxates and Union Territories, including special non-Plan assistance to States for meeting gaps in resources, assistance for natural calamities, short-term loans for purchase *o*\ fertilisers, etc., and loans out of small savings collections, Rs. 202 crores for loans to others, Rs, 328 crores for schemes of Government Trading, which are, in fact, more than offset by recoveries, Rs. 32 crores for Border Roads and the rest being spread over a number of heads.

Other details of the disbursements have been given in (lie Budget documents circulated to the hon. Members. The House had an opportunity of a general discussion oil

the Budget. I do not, therefore propose to take the time of the House in explaining further the provisions included in the Bill.

Sir, I move.

The question was proposed.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, लोकसभा ने जो विभिन्न मंत्रालयों की ग्रांट्स थीं उनको पास कर दिया और अप्रोप्रियेशन बिल उनके सम्बन्ध में आज हमारे सामने है । मंत्री जी ने मोटे तौर से कुछ बातें बताईं कि किन-किन मोटी मोटी बातों में कितना कितना पैसा बजट में रखा गया है ।

श्रीमन्, ग्रांट्स पास हो गई । हम सब जानते हैं कि जितने समय में ग्रांट्स पास होती हैं पार्लियामेंट को उतना मौका नहीं मिलता है कि वह ज्यादा बारीकी से ऐस्टिमेट्स की छानबीन कर सकें । इसलिए मैं सबसे पहले यह दरख्वास्त करूंगा वित्त मंत्री जी से कि आपका बजट पास हो गया, आपकी ग्रांट्स पास हो गईं, अप्रोप्रियेशन बिल भी पास हो ही गया, लेकिन इस बात को देखने की जरूरत है कि जो पैसा विभिन्न मंत्रालयों को दिया गया है उन मंत्रालयों पर इस बात की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह बारीकी से इसकी छानबीन करें और आज के जमाने में जैसा कि प्राइम मिनिस्टर भी ठीक ही कहती हैं कि हम आर्थिक विषमता की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो हर मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है कि वह इस बात की कोशिश करे कि उसके विभाग में जो फिजूलखर्ची है वह कम हो । अगर पूर्ण रूप से समाप्त न हो तो कम जरूर हो ।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि जो अनप्रोडक्टिव ऐक्सपेंडीचर है जो कि बढ़ता जाता है, बार बार सरकार का ध्यान दिलाया गया है, उसके अन्दर तेजी से कमी करने की आवश्यकता है । उसको कम करना चाहिए । आज जब कि हम बहुत जोर से समाजवाद की बात करते हैं, सुखे की बात करते हैं, अपने देश में गरीबी की बात करते हैं, मैं यह जानता हूं कि मेरी बात का सरकार पर असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमको, हमसे मतलब है सरकार और तमाम तत्वों को चाहे मिनिस्टर हों, चाहे मेम्बर पार्लियामेंट हों, चाहे सरकारी अफसरान हों उनको अपनी जिन्दगी में सादगी लानी चाहिए । श्रीमन्, एम्पाला कार और एयर कंडीशन में बैठकर समाजवाद की बात करना ठीक नहीं लगता है । इसलिए मैं फिर जोर देना चाहता हूं कि वैस्टेज को कम किया जाए और सादगी लाई जाए ।

एक या दो दिन हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कुछ टैक्सेज में कमी की घोषणा की, मैं उसका स्वागत करता हूं, हालांकि उससे कोई बहुत बड़ी राहत जन-साधारण को प्राप्त होने वाली नहीं है । पिछले सत्र में जो हमारा बजट के ऊपर साधारण वाद-विवाद हुआ था, उसके बाद पे-कमीशन की रिपोर्ट आई । उसके ऊपर, मुझको नहीं मालूम कि सरकार कितना वक्त लेगी, उस कमीशन की रिपोर्ट की किन-किन बातों को मानेगी और यह भी पूर्णतया पता नहीं है कि उसका कितना भार–140 करोड़, 130 या 150 करोड़ सरकारी खजाने पर पड़ने वाला है । इस कमीशन के बारे में मुझे इस बात की तकलीफ हुई–बड़े जिम्मेदार मैम्बर थे कमीशन के, कमीशन की रिपोर्ट आई, अच्छा होता कि वह पूर्णतया अपने मतभेद, आपस के झगड़े रिपोर्ट आने से पहले तय कर लेते । अगर रिपोर्ट आने के बाद जो पब्लिक कंट्रोवर्सी सारे अखबारों में हुई–कुछ मैम्बरान ने आई० ए० एस० के कैडर को देखा, टेक्नाक्रेट्स और नान टेक्नोक्रेट्स को देखा–श्रीमन् आपस में जो वाद-विवाद हुआ मुझे इस बात का दुःख है कि उससे न कमीशन का स्टेचर बढ़ा, न मैम्बर साहबान का स्टेचर बढ़ा, न उन सर्विसेज का जिनके बारे में वाद-विवाद हुआ है स्टेचर बढ़ा है । इस लिए मैं चाहता हूं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वे इस तरह की बातों को न करें तो अच्छा है ।

अब मैं श्रीमन् खाद्य के ऊपर आता हूं । मैंने शुरू में कहा था और मैं आज फिर उसको कहता हूं कि आपने फूड ग्रेन टेक ओवर किया, जहां तक उसके सिद्धान्त का प्रश्न है उसमें न मुझे पहले मतभेद था और न आज है, लेकिन मैं केवल यह कहना

[श्री नवल किशोर]

चाहता हूं कि जो बातें आप से कही गई थी उन बातों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया । आज स्थिति क्या है । आपने मैक्सिकन गेहूं का भाव 76 रु० फी क्विंटल रखा है और देशी गेहूं का भाव शायद 81 रु० फी क्विंटल रखा है । वैसे कहीं कहीं उसका भी भाव 76 रु० फी क्विंटल है । श्रीमन्, आप भी काश्तकार हैं जिस को अंग्रेजी में कहते हैं कल्टीवेटर । इस लिए आप जानते होंगे कि आज खाद की कीमत बढ़ रही है, आबपाशी की दरें बढ़ रही हैं । उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबिले में उसकी दरें डेवढ़ी दुगनी हो गई है, फिर भी किसान को पानी मिल नहीं रहा है । बिजली का ब्रेक डाउन हो गया है । तीन चार घंटे से ज्यादा उसको बिजली मिल नहीं रही है । लोहे की कीमत बढ़ गई है । सीमेंट की कीमत बढ़ गई है । किसान की जरूरत की हर चीज की कीमत बढ़ गई है । आज उसको डीजल नहीं मिलता । ट्रैक्टर के दाम दुगुने और तिगुने हो गये हैं जोकि यह ठीक है कि वे बड़े काश्तकारों के पास हैं । इसके बावजूद गेहूं के भाव पिछले तीन सालों से वही 76 के 76 रु० फी क्विंटल चले आ रहे हैं । मैं उत्तर प्रदेश गया तो वहां मैंने देखा कि चने का भाव 135 रु० फी क्विंटल है । आज अपाकी जो अरहर है उसका भाव 135 रु० क्विंटल है । मसूर के भाव उससे भी ज्यादा है । बाजरे के दाम 80, 85, 90 रु० क्विंटल है । मैसूर और महाराष्ट्र में उसके भाव कितने हैं उसकी बात मैं नहीं करता । तो जब मोटे अनाज की कीमत 85 रु० क्विंटल से 135 रु० क्विंटल तक है तब कैसे हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि किसान 76 रु० में आप को गेहूं दे देगा । अगर आप यह चाहते हैं कि किसान 76 रु० क्विंटल के हिसाब से आप को गेहूं दे तो आप उसकी आवश्यकता की चीजों को सबसीडाइज्ड रेट पर उसको दीजिये और उनको किसानों तक पहुंचाने का इन्तजाम कीजिये । लेकिन वैसा हो नहीं सकता । इस लिए आज हालत यह है कि दिल्ली में सारा स्टाक खाली पड़ा हुआ है । अगर आप को अपने प्रोक्योरमेंट को कामियाब करना है, तो मैं चाहता हूं कि जो आपने स्कीम चलाई है उसमें आप कामियाब हों, लेकिन एक बात के लिए मैं आप को आगाह करना चाहता हूं कि आप किसान को अच्छी कीमत से इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर पुलिस का उसके ऊपर दबाव डाला तो वैसे ही लां ऐंड आर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, वह और ज्यादा खराब हो जायगी । इस लिए मैं आपसे कहना चहता हूं कि आज सुबह ही वादविवाद हुआ । गणेश साहब थे नहीं । आप की डिस्ट्रिब्युशन की मशीनरी का ब्रेक डाउन हो चुका है । आज शुगर को आप लीजिये । आप को बड़ा दर्द है गरीब आदमी का, किसान का मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि आज गांवों के अन्दर जो शुगर का कोटा आप देते हैं उसका मुश्किल से 10 परसेंट भी गांवों के आदमियों के पास पहुंच नहीं पाता है, वहीं का वहीं ब्लैक हो जाता है । आप ने एफ० सी० आई० को जब से काम दिया है सात आठ दिन तक वहां का दूकानदार जिसको छः बोरियां शुगर की आप देते हैं उसके पास कोटा पहुंच नहीं पाता है । कभी पहुंचता है तो रात में पहुंचता है और कहीं गोडाउन्स भी नहीं है । इसी तरह से सीमेंट के सम्बन्ध में जैसा कि बाबुभाई जी ने बताया कि 12 रु० की बोरी 32 रु० में बम्बई में बिक रही है । हमारे वित्त मंत्री महाराष्ट्र से आते हैं । उत्तर प्रदेश में भी सीमेंट का भाव 24 से 28 रु० बोरी है । मैं सीमेंट का अभाव तब मान सकता था जब वह किसी भाव पर न मिले । लेकिन आज हालत यह है कि 32 रु० बोरी के हिसाब से जितनी भी सीमेंट कोई चाहे उसको उपलब्ध हो सकती है । सी० पी० डब्लू डी० की हजारों बोरियां बाजार में बिक रही हैं । लेकिन 12 रु० के कंट्रोल रेट पर आप सीमेंट नहीं दे सकते हैं । यह आज स्थिति है । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर यही खयाल है कि हमने सब टेक ओवर कर लिया तो उससे समाजवाद आ जायगा तो मुझको आप से कुछ नहीं कहना है । आप भ्रम की दुनिया में रहते रहिये । लेकिन अगर वाकई आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप को अपनी मशीनरी को टाइट-अप करना पड़ेगा । इतना ही नहीं, मैसूर की शिकायत है कि वहां सूखा पड़ा हुआ है । महाराष्ट्र की शिकायत है और गोरे साहब ने कहा था कि महाराष्ट्र में गेहूं चार या पांच रुपये किलो तक बिक रहा है ।

मैसूर की जितनी डिमांड है उस का पचास परसेंट भी आप उस को नहीं दे पा रहे हैं। आपने कहा कि हम दस मिलियन टन प्रोक्योर करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं कि आप इतना कर पायेंगे, क्योंकि जैसे आप के बफर स्टॉक के आंकड़े गलत थे उसी तरह से पैदावार के जो आंकड़े आप को दिये गये हैं वह भी गलत हैं और उन में आप को धोखा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात मैं जानता हूं। वहां गेहूं की पैदावार इतनी नहीं है जितने के आप के पास आंकड़े हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि 10 मिलियन टन प्रोक्योर हो भी जायगा तो कल जैसा कि सवाल किया गया था कि 22 करोड़ लोग जो कि पावर्टी लाइन के नीचे के हैं उन को तो आप को गल्ला देना ही होगा। तो इस के मायने यह हैं कि केवल चार किलो गल्ला आप एक माह में एक व्यक्ति को दे सकेंगे। क्या आप यह भी कर पायेंगे? फिर उस गरीब आदमी के लिए जिस के पास खाने को नहीं है क्या यह चार किलो एक माह के लिये काफी होगा, और अगर नहीं होगा तो बाकी चार किलो के बाद, चार या आठ किलो जो उस को और आवश्यकता है उसके लिए आप ने क्या किया है? तो इस तरफ भी मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब तक बिजली की स्थिति आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक आबपाशी की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक मुझे यकीन है कि खाद्य की स्थिति ठीक होने वाली नहीं है।

अब इस के बाद मैं एजूकेशन की बात कहना चाहता हूं। एजूकेशन भी बहुत आवश्यक चीज है। जिस समय यहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विधेयक आया हाउस में, उस समय सब लोगों ने मांग की कि इस को आप एक ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दें। लेकिन उस समय कहा गया कि नहीं, इस बात की बड़ी मांग है कि इसको जल्दी से पास कर दिया जाये। उस को पास कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इतने महीने गुजर गये, क्या उस बिल का इम्पलीमेंटेशन हुआ? उस को ले कर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गयी है सारे देश में।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : उस को अपना एलेक्शन मैनीफेस्टो बनायेंगे।

श्री नवल किशोर : और आज वह यूनिवर्सिटी बंद है और बन्द क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स चाहते थे कि एक दीन साहब जिन्होंने स्टूडेंट्स के खिलाफ और इस एक्ट के फेवर में कोई बयान दे दिया था या कोई बात कह दी थी, उनको हटा दिया जाये। वाइस चांसलर ने कहा कि हम उन को हटा देंगे। उन्होंने कह तो दिया, लेकिन न उनको हटाने की हिम्मत और न अपने वायदे से हटने की हिम्मत और उस के बीच में वह यूनिवर्सिटी बन्द पड़ी हुई है। बनारस की क्या स्थिति है वह भी आप देख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐक्ट की मांग एक जमाने से है, लेकिन अभी तक वह ऐक्ट नहीं आया। दिल्ली का आपने एजूकेशन बिल भी पास कर दिया टीचर्स के लिए, लेकिन जो एक मांग थी कांप्रेहेंसिव बिल की, वह अभी तक नहीं आया है। तो यह स्थिति एजूकेशन की है कि हर जगह जहां देखिए कयास ही कयास दिखायी देता है।

डिफेंस में अभी आप ने बताया कि हमने 1600 करोड़ रुपया रखा है। यह अच्छी बात है। आज जो स्थिति है उसको देखते हुए डिफेंस के लिए यह पैसा भी काफी नहीं है। इस साल या पिछले दो, तीन सालों से नेवी पर हमने कुछ जोर दिया है और सही जोर दिया है। हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। इंडियन ओशन को आप चाहते हैं और ठीक चाहते हैं कि वह एक पीसफुल जोन रहे। लेकिन उस के लिए आवश्यक यह है कि आप की नेवी मजबूत हो। आज पाकिस्तान का खतरा है। अमरीका का रुख भी अच्छा नहीं है और जो ईरान है उस की नीयत भी यह है कि वह इंडियन ओशन में अपना असर, इंफ्ल्युयेंस कायम करे। तो ऐसी हालत में पैसे की ज्यादा आवश्यकता है। आज पाकिस्तान का जिस तेजी से एयर फोर्स बिल्ड अप हो रहा है चाइना और अमरीका की मदद से और जैसा कि आप के जनरल्स भी कह रहे हैं उस में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है और पाकिस्तान ने नयी चार डिवीजनें बनायी हैं। प्रिजनर्स आफ वार का डिसीजन तो जब होगा

[श्री नवल किशोर]

तब होगा, लेकिन इस 1971 की जंग के बाद चार नये डिवीजन उन्होंने बना लिये हैं। इन चीजों को देखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात पर मुतमईन है *Time bell rings* श्रीमन् अभी तो मैंने शुरू किया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर मुतमईन है कि जो अंदेशा है उस को देखते हुए यह बजट काफी है?

श्रीमन् शिमला एग्रीमेंट हुआ, हम सब ने उसका स्वागत किया मगर आज उसका फेट क्या है। आज भुट्टो साहब का एटीट्यूड क्या है? अभी बंगला देश और हिन्दुस्तान ने एक मैगनानिमस आफर दिया प्रिजनर्स आफ वार के बारे में, बंगला देश में जो नान-बंगालीज हैं उनको पाकिस्तान भेजने के बारे में और जो पाकिस्तान में बंगालीज हैं उनको वापिस लाने के बारे में, मगर लगातार एक इंट्रांजिएंस का एटीट्यूड है मिस्टर भुट्टो का और हमको पता नहीं चल पा रहा है कि हम कहां हैं सही है कि हम अपना आफर दे देते हैं, बहुत अच्छा आफर दे देते हैं, उससे हमारी उदारता भी जाहिर होती है मगर उस उदारता का कोई असर पाकिस्तान पर होता हो ऐसी बात मैं नहीं पाता। अभी हमारी प्राइम मिनिस्टर सीलोन गई थीं, उन्होंने वहां तय किया कि वहां जो इंडियन्स स्टेटलैस हैं, जो कि 35 हजार हर साल आने को थे उसमें 10 परसेंट का इजाफा हो जायेगा और वह हिन्दुस्तान के अन्दर जल्दी आ जायेंगे ताकि वह जो टाइम-शेड्यूल है वह अपनी जगह पर बना रहे और इसी तरह से किच्छा टिब्बू आइलैंड के बारे में है कि दोनों देश मिलकर फिर से सभी पहलू से इसको देखें मैं नहीं कहता कि आपमें कोई कमजोरी है लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि हर एक कम्युनिके के अन्दर हम कुछ थोड़ा उदार ज्यादा मैगनानिमस, हो गये हैं, हर कंट्री के साथ चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो हिन्दुस्तान कुछ दबता जाता है जहां तक कि उसके इन्ट्रेस्ट का संबंध है।

श्रीमन्, पोलिटिकल पेंशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आपने एनाउंस किया कि हम उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को पेंशन देंगे जिनकी छ: महीने से ज्यादा की जेल है। आज महीनों हो गये, हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, उनकी स्क्रुटिनी नहीं हुई है, जिनका जेल से कोई वास्ता नहीं था उनको पेंशन मिल गई है, जो रूलिंग पार्टी का है उसको पांच सौ रुपये और जो पार्टी का नहीं है उसको केवल दो सौ रुपये। तो ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं यदि इनमें भी डिसक्रिमिनेशन होगा पार्टी बेसिस पर तो मैं समझता हूं कि जो इसकी स्प्रिट है वह अपनी जगह पर खत्म हो जायेगी। यही स्थिति ताम्रपत्रों की है।

श्रीमन्, फेमिली प्लानिंग पर बहुत जोर दिया जाता है। मैं हंडरेड परसेंट इसके हक में हूं। मुझे पता नहीं कि गणेश साहब ने किया है या नहीं लेकिन मैं उसके हक में हूं।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा): आपने किया है।

श्री नवल किशोर: मेरा तो वैसे ही हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी आंकड़े दिये जाते हैं वह ठीक नहीं है। मुझे उत्तर प्रदेश का एक्सपीरियंस है, कुल मुश्किल से 15 या 20 परसेंट जेनविन केसेज होते हैं वर्ना 75 से 80 परसेंट केसेज बिल्कुल होक्स होते हैं और जैसा कि मेरे एक दोस्त बैठे हुए हैं बुजुर्ग, बड़े भाई, श्री डाह्या भाई पटेल या श्री उमा शंकर दीक्षित, इनके एज-ग्रुप के आदमियों को वहां फेमिली प्लानिंग होती है जो कि वैसे ही स्वयं उस जगह पर पहुंच गए हैं, जहां उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्रीमन्, कपड़े की हालत यह है कि 107 टेक्सटाइल मिल्स का आपने टेक-ओवर कर लिया, मगर स्थिति नहीं बदली। पटेल साहब बैठे हुए हैं – अहमदाबाद में बिजली की कमी के कारण 150 करोड़ रुपये का उत्पादन में घाटा हुआ है और केवल अहमदाबाद के अन्दर ढाई लाख मजदूर बेकार हुये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो वायदा किया था कि मोटा कपड़ा सस्ती कीमत पर किसानों को और गरीब आदमियों को देंगे उस वायदे का क्या हुआ। आज टेक्सटाइल में 30 परसेंट कीमतें बढ़ गई हैं। मगर कपास की 40 परसेंट कीमतें घटी हैं। मैं इस वास्ते इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि यह गरीबी हटाने

का तरीका नहीं है। श्रीमन् जहां तक कि व्यवस्था का प्रश्न है, ला एंड आर्डर का प्रश्न है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाय वह थोड़ा है। बिदर्भ बन्द हुआ, उसमें एम०एल०ए० पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया किसी तरह गरीब बच गया मगर सब-इंस्पेक्टर मारा गया, दिल्ली में दुकानों को, प्रेसों को लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है तो उसकी स्थिति अपनी जगह है। श्रीमन्, आप हर चीज का नेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, सब का कर दीजिए लेकिन जब शुगर नेशनलाइजेशन का सवाल आता है तो चुप हो जाते हैं हालांकि आपका बम्बई का प्रस्ताव है। कहते हैं, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। अखबारों में छपा है कि कमेटी के मेम्बर्स के व्यूज अलग अलग डिवाइडेड हैं, उसके आधे मेम्बर कहना चाहते हैं कि होना चाहिये और आधे मेम्बर कहना चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए। सरकार ने ऐसी कमेटी बनाई है, बहुत बढ़िया कमेटी बनाई है कि वह किसी स्पष्ट फैसले पर पहुंचेगी ही नहीं। तो जहां राष्ट्रीयकरण होना चाहिए वहां करते नहीं हैं और अगर करते हैं तो चाहे कपड़ा हो, चाहे कोयला हो, चाहे स्टील हो, कीमतें कहीं कम नहीं हो रही हैं, यहां तक कि मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जिस मारुति कार का कारखाना चौधरी रणबीर सिंह के हरियाणे में लग गया है उस कार की कीमत वही होगी जो और कारों की होगी। क्या फायदा होगा ऐसी छोटी कार से ?

श्री रणबीर सिंह : नहीं, नहीं।

श्री नवल किशोर : नहीं, नहीं कुछ मत कहो। श्रीमन्, 2 बातें कह कर खत्म करूंगा। तेल की कमी है—डीजल की, मिट्टी के तेल की कमी है। बहुत दिनों से मांग है कि फारेन आइल कम्पनीज को नेशनलाइज किया जाय। गणेश जी, आप तो अल्ट्रा सोशलिस्ट हैं, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप उन कम्पनीज को भी नेशनलाइज करेंगे ?

आखिरी बात कहना चाहता हूं। जनतन्त्र के लिए इस बात की खास आवश्यकता है कि मजबूत पार्लियामेंट हो, इन्डिपेंडेंट प्रेस हो, इन्डिपेंडेंट जुडिशरी हो और स्ट्रांग पब्लिक ओपीनियन हो। अब पार्लियामेंट आज जितनी स्ट्रांग है, हम और आप जानते हैं, क्योंकि अपोजिशन कमजोर है, डिवाइडेड है। शिक्षा की कमी के कारण पब्लिक ओपीनियन बहुत स्ट्रांग हो नहीं पाती, प्रेस की आजादी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। यह जो आपका प्रस्ताव आने वाला है, डिफ्यूजन आफ ओनरशिप, इससे जो कुछ प्रेस की इन्डिपेंडेंस है उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन आपने कमाल कर दिया कि हिन्दुस्तान का जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है उसको डाउनग्रेड कर दिया, डेनीग्रेड कर दिया, डिमोरेलाइज कर दिया। उसकी इन्डिपेंडेंस के ऊपर कुठाराघात कर दिया। मुझे हंसी आती है, प्राइम मिनिस्टर कहते है कि जो यह कहते हैं कि हम डिमोक्रेसी के खिलाफ हैं वे डिमोक्रेसी को जानते नहीं, जो कहते है हम कन्ट्री को कम्युनिज्म की तरफ ले जा रहे हैं वे कम्युनिज्म को नहीं जानते और जो कहते हैं समाजवाद इस तरह से नहीं आएगा वे समाजवाद को नहीं जानते। मुझे याद है, नवाब रामपुर कहते थे कि जो मां बदौलत कहते हैं वही कानून है। तो हिन्दुस्तान में 55 करोड़ लोगों में से एक ही व्यक्ति है जो जानता है कि डेमोक्रेसी क्या है, जो जानता है कि सोशलिज्म क्या है, जो जानता है कि कम्युनिज्म क्या है, जो जानता है कि सेक्युलरिज्म क्या है। For any one person it is too much to presume.

श्री महाबीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : जानता नहीं, जानती है।

श्री नवल किशोर : जानता और जानती में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उन्हीं को इस बात का हक है कि यह सार्टिफिकेट दें कि कौन आदमी डिमोक्रेट है, कौन सोशलिस्ट है, कौन सेक्यूलर है। ऐसा कहीं किसी देश में नहीं होता। और, दुहाई दी गई कि ला कमीशन की रिकमंडेशन है। 15 साल के बाद होश आया ला कमीशन की रिकमंडेशन का। मंगल के दिन फैसला होता है और दूसरे दिन को अपौइन्टमेंट हो जाता है।

[श्री नवल किशोर]

एक नहीं, तीन-तीन आदमी सुपरसीड हो जाते है मेरिट के नाम पर। मेरिट यह है जो हां में हां मिलाए, वह प्रोग्रेसिव्ह है और .....

श्री रणबीर सिंह : जो सही फैसला दे।

श्री नवल किशोर : सोशल जस्टिस और इक्विटी को समझना है और जो हां में हां न मिलाए वह हमारे विरुद्ध है, हमारे विपरीत है इसलिए प्रतिक्रियावादी है। मैं आपसे बड़ी अदब से कहना चाहूंगा—आग से खेलना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। हर चीज में पेशेन्स की भी एक हद हुआ करती है। लिहाजा चौधरी रणबीर सिंह से कहना चाहता हूं, इस समय उनके ऊपर तो जादू है समाजवाद का, क्योंकि उनको तो छू दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, अगर वह टाटा को छू दें तो टाटा भी सबसे बड़ा समाजवादी हो जाए, बिड़ला भी समाजवादी हो जाए। मैं तो जनाब, पैदाइश से सोशलिस्ट हूं, जिसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास ही समाजवाद में है। मगर मैं मर्सीडीज और इम्पाला में बैठकर समाजवाद की बात नहीं करता हूं। तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से अब कमिटेड जजेज की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है, अगर इसको नहीं रोका गया, तो हिन्दुस्तान में न डिमोक्रेसी रहेगी, न हिन्दुस्तान में समाजवाद रहेगा और आज उधर के हमारे साथी हां में हां भी मिला सकते हैं, थप-थप भी कर सकते हैं, मगर खामियाजा उनको भी उठाना पड़ेगा।

श्री महाबीर त्यागी : उन साथियों ने काला चश्मा लगा रखा है।

श्री रणबीर सिंह : आपका सफेद भी काला हो गया।

श्री नवल किशोर : यह जो आपका इन्फ्लेशन है – आखीर बात कह कर खत्म करता हूं एक सैंटेंस में कह कर—यह इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, गणेश साहब इस बात को मानेंगे कि इस बजट के डिसकशन के बाद भी कीमतें बढ़ी हैं घटी नहीं हैं। अगर यही स्पीड कायम रही कीमतों के बढ़ने की तो जो चौथे और पांचवें प्लान के टार्गेट हैं, वे पूरे होने वाले नहीं हैं। 3 P.M.

आपका मनी सप्लाई तो 10 परसेंट बढ़ते चला जाता है और गुड्स सप्लाई केवल तीन परसेंट ही बढ़ता है। इस तरह से यह जो तीन और दस का रेशो है उसके कारण ही देश में इंफ्लेशन बढ़ता है और चीजों की कीमत बढ़ती चली जाती है। तो श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो एप्रोप्रिएशन बिल है वह तो पास हो जायगा, लेकिन जो आपने जनता को वायदे किये हैं वह आप कब तक पूरा करने वाले हैं। मैं इस बारे में कोई ताना नहीं दे रहा हूं बल्कि मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप इस बात को संजीदगी से सोचें। आप पावर में है जिसके कारण आप में जो एक तरह का जोम भर गया है उसको आपको खत्म करना चाहिए। मैं चौधरी साहब की बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्रगतिशीलता के ठेकेदार आप ही नहीं है। इस तरह की जो बात आपके दिमाग में है उसको आप निकाल दीजिए। आपको देश में जो प्रगतिशील तत्व है, उनको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए कि जो विरोधी पक्ष में लोग बैठे हैं वे प्रतिक्रियावादी है। इस तरह की स्टुपिड नान सेन्सिबिल बातें आपको नहीं कहनी चाहिए। इस देश में और इस तरफ से बैठे हुए बहुत से ऐसे आदमी हैं जो आप से भी अच्छे समाजवादी है और आप उनकी सहायता लेकर आगे जा सकते हैं। अगर आपने मनमानी की तब—

"There would be nothing but chaos and disaster and, Mr.Mehta, in spite of best wishes, this country going to be your stagnant so far as its economy is concerned."

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उपसभाध्यक्ष महोदय हमारे वित्त मंत्री जी ने कई बार किसानों की समस्या के बारे में प्रकाश डाला है और देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वह आज किसानों की ही है। उनकी जो समस्या है वह खेती में अच्छी पैदावार करना है, किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध होने चाहिये, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए तथा उन्हें इन चीजों के लिए और दूसरी बातों के लिए बैंकों तथा सरकार से ऋण प्राप्त होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार जो किसानों की

अपने को जमानतदार कहती है उसने देश के किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए जो धनराशि की आवश्यकता होती है उसे दिलाने में वह सहायक नहीं हो सकी है चाहे वह बैंकों द्वारा हो या सहकारी बैंकों द्वारा हो। सरकार इस माने भी अभी तक असफल रही है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस ओर सरकार ने कहां तक प्रगति की है, वह उसके बारे में बतलायें।

श्रीमन्, जब मौसम ठीक रहता है तो हमारी सरकार भी हरित क्रांति की बात करती है, लेकिन मौसम खराब होने के साथ साथ उसकी हरित क्रांति समाप्त हो जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हरित क्रांति तब तक नहीं आ सकती जब तक देश में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न की जाये। देश में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो और इसके लिए सरकार को तथा वित्त मंत्रालय को सिंचाई की योजना की ओर ध्यान देना चाहिए। वैसे हमारे सिंचाई मंत्री जी दूसरे भगीरथ बनने का प्रयास कर रहे हैं। पहिले भगीरथ तो गंगा को स्वर्ग से लाये और शिव जी की जटा से छुड़ाकर जमीन पर लाये। आज हमारे सिंचाई मंत्री अब दूसरे भगीरथ बनना चाहते हैं और वे गंगा और कावेरी को मिलाना चाहते हैं और उसके पानी का उपयोग धार्मिक तथा सिंचाई के काम में लाना चाहते हैं। पता नहीं हमारे वित्त मंत्री जी का इस कार्य में कितना सहयोग होगा और वह इस कार्य के लिए कितने पैसे की व्यवस्था कर सकेंगे। लेकिन श्रीमन् मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई नदी क्यों न हो, चाहे वह गंगा नदी हो या कोई भी नदी हो, सरकार ने देश में नदियों के पानी का उपयोग जनता की भलाई के काम में बहुत कम किया है। नदियों का जो पानी होता है वह सिंचाई के काम में आ सकता है, यातायात नदियों द्वारा हो सकता है और बिजली के उत्पादन में पानी की सहायता ली जा सकती है तथा पानी के बहाव में नदी सहायक हो सकती है।

हमारे देश की जो नदियां हैं वे बड़े बड़े शहरों की शोभा बढ़ाती हैं और वहां के लोगों को पीने के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। लेकिन हमारे देश की जो सबसे बड़ी नदी गंगा है उसका हमारी सरकार ने अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया है। इस नदी के बाढ़ से आज तक कितने लोग प्रभावित हो चुके हैं और हर साल कितने होते हैं इसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई आकड़े तैयार नहीं किये और न ही इस बाढ़ से जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए कोई प्रबन्ध किया है। तो मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें और देश में जो हमारी नदियां हैं उनके पानी का उपयोग जनता के लिए किस तरह से हो सकता है उसके लिए प्रबन्ध करें। इसके अलावा जो हमारे यहां अन्डर ग्राउन्ड पानी है उसका भी उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, उसके बारे में भी ध्यान दें। सचमुच में सूखे का, अकाल का कोई मुकाबला हो सकता है तो इसी के द्वारा हो सकता है और इस ओर मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश में सैकड़े में जो ९५ फीसदी छोटे किसान हैं वे सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन वे बैंक को सीक्योरिटी नहीं दे सकते, सरकार हर बार कहती है कि वह जमानतदार बन कर उनको सहयोग देंगे, इस बारे में सरकार कहां तक सफल हुई है और आगे क्या करने का विचार रखती है यह मैं जानना चाहूंगा।

श्रीमन्, हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने उल्लेख किया कि वे राष्ट्रीयकरण की नीति से असहमत नहीं हैं लेकिन उसके विधि-विधान से असहमत हैं। इस राष्ट्रीयकरण की विधि से अगर किसानों को लाभकारी उत्पादक मूल्य मिलता तो शायद देश में किसी को एतराज न होता और अगर उपभोक्ता को भी अनाज सस्ते दाम पर उपलब्ध होता तब भी उनका विरोध न होता, लेकिन यह बात अब सबके सामने प्रत्यक्ष हो चुकी है कि इनकी जो फेयर प्राइस शाप्स हैं उन पर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन मशीनरी अनाज ठीक प्रकार भेज नहीं सकती है। आपने देखा कि इनकी फेयर प्राइस शाप्स

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

में दिल्ली के मिलों में धतूरा मिलता है तो हमारे मुंगेर जिले में लोहे का कतरन मिला। वह अनाज भी फेयर प्राइस शाप पर प्राप्त होता नहीं। गेहूं के स्टाक के बारे में कहा कि लम्बी लम्बी चौड़ी-चौड़ी बातें राज्य के मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों की है। मैं बिहार की बात कहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री श्री केदार पांडे दिल्ली आते है और जोरदार शब्दों में कहते है कि हम इतना प्रोक्योरमेंट करेंगे। उन्हीं के दूसरे मंत्री श्री बोदरा जी कहते है कि बिहार में गेहूं की पैदावार हुई ही नहीं और प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता। दोनों मंत्रियों की बात में तालमेल नहीं बैठता।

श्रीमन्, जले पर नमक छिड़कने के समान बिहार सरकार ने किसानों पर लेवी लगाने की बात की है। किसानों को कौन सी सुविधा देने के बाद लेवी लगाने की बात की जा रही है। बिजली की बात आपने सुनी, वह मिलती नहीं। खाद का भी वही हाल है। सरकार कहती है कि खाद्यान्न में कमी हुई है तो उसको पूरा करने के लिए सारे उपाय सरकार करेगी। यह तो उसी तरह हुआ कि जैसे गेहूं की बुवाई हो रही हो तब नलकूप लगाना शुरू किया जाय। हरियाणा में जहां सब गांवों में बिजली पहुंच गई थी, जहां बिजली दी जा सकती थी, वहां भी बिजली बन्द हो गई। खाद किसानों को मिली नहीं। जब गेहूं में बीमारी लगी तो दवा नहीं मिली। किस तरह से दवा छिड़ककर बीमारी का इलाज किया जाता। जब हम डेढ़ी दुगने दाम में दवा खरीदते हैं तो उनको कैसे मिलती। फिर दूसरी जो जीवनोपयोगी चीजें हैं उनका क्या उपाय है। गेहूं के दाम तो आप तय करते है 76 रुपये क्विन्टल। बार-बार कहा गया कि दर तय करने में कृषि विश्वविद्यालय के अध्यापकों का, किसानों के प्रतिनिधियों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन आज तक उस ओर हमारी सरकार का ध्यान गया नहीं जिसके कारण कृषि उत्पादक को जो लाभकारी दर मिलनी चाहिए वह नहीं मिली। श्रीमन्, इसीलिए अनाज का व्यापार का राष्ट्रीयकरण चाहें या न चाहें वह असफल तो होगा ही, श्रीमन् सबसे बड़ी भयंकर देश में अन्न की जो स्थिति नजर आ रही है, इस राष्ट्रीयकरण के बाद कहीं पर अनाज पूरा आएगा और कहीं पर अनाज के बिना लोगों में हाहाकार मच जाएगा। मैंने उस समय भी पूछा था कि कितना अनाज मरप्लस होगा, उसको खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है और मशीनरी जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वह सरकार के पास कैसी है, उसको भी सही आधार नहीं दिया गया और उसके प्रतिफल आज देश में आन्दोलन हो रहे हैं। जगह जगह लोग परेशानी में पड़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार से इस बात का आग्रह करूंगा कि सरकार इस पर प्रकाश डाले कि जिससे लोगों को आश्वासन हो कि सुलभ दर पर उन्हें अनाज प्राप्त होगा और साथ ही किसानों को भी सरकार लाभकारी दाम देने का प्रयास करेगी।

आज देश में सिर्फ अन्न को ही लेकर नहीं बल्कि अनेक बातों को लेकर प्रशासन की स्थिति बड़ी डावाडोल है। लूट की खबर राजधानी में प्रातःकाल देखी और हमारे लेबर की हड़ताल में वह बातें बढ़कर गृह मंत्रालय की स्थिति में आई कि सरकार भी इस बात में इंटेंगिल हो जाती है कि किस प्रकार लूट-खसोट हो और पुलिस एकमात्र तमाशा रह जाता है। दिल्ली में जो लूट-मार चोरी-डकैती की भरमार बढ़ी है उसका एक डाटा निकला था और उससे लगता है कि दिन दूनी रात चौगुनी लूट मार, चोरी के केस नित्य प्रति बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासनिक स्थिति इतनी अक्षम हो गई है, पता नहीं यही स्थिति रही तो इस देश का दुर्भाग्य किस प्रकार ठीक होगा। हम जानना चाहेंगे कि मंत्री जी इस ओर अपना ध्यान देंगे और बतायेंगे कि सचमुच में देश की माली स्थिति बिगड़ती नहीं जा रही है बल्कि उनकी नजर में सुधरती जा रही है, यह हम जानना चाहेंगे।

तीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सुपरसीड किया गया और वे इस्तीफा भी दे दिये। सरकार का कहना है कि न्याय गरीबों को सस्ता मिलेगा। तीन न्यायाधीशों को सुपरसीड

करने के बाद न्याय सस्ता हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में तो लगता है कि प्रदेश के हाई कोर्टों में या जिलाधीश के न्यायालय में उनको भी सुपरसीड कराया जाएगा, तभी मुझे लगता है कि गरीबों को इंसाफ सस्ता मिलेगा। अभी तो इंसाफ पैसे के द्वारा खरीदा जाता है और अनावश्यक विलम्ब से मिलता है। यह वस्तु-स्थिति सबके सामने है। लेकिन आज हमारी सरकार और सरकार के मुख्य वक्ता कह रहे हैं कि वह स्थिति जिससे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने जाते थे उस स्थिति से न्याय लोगों को नहीं मिलता। लेकिन सुपरसेशन की स्थिति में लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा, यह बात तो अभी तक समझ में नहीं आई। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय इस बात को जानकारी जरूर सदन को करायेंगे कि इस सुपर-सेशन में किस प्रकार सस्ता न्याय छिपा हुआ है। हमारे प्रधान मंत्री का कहना है कि ला-कमीशन के हिसाब से उन्होंने ऐसा किया है। हो सकता है ला-कमीशन ने कहा कि एक ही क्राइटेरिया या सीनियारिटी ही उसका मुख्य क्राइटेरिया नहीं होगा। तो एक के बारे में अगर कुछ बात होती तो बात समझ में आती, लेकिन किस प्रकार तीन-तीन के ऊपर लागू हुआ और चौथे पर लागू क्यों नहीं हुआ, यह बात अभी किसी के दिमाग में साफ नहीं हुई। वैसे हमारी जो जान-कारी है, ऐसे उनमें न्यायाधीश हैं जो दो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जिनको प्रशासन और न्याय का ज्ञान है। तीसरे का भी काफी अनुभव है और चौथे के बारे में बहुत खोज करने के बाद भी यह पता नहीं लगता कि कौन सी क्वालिटी चमककर आई जिसके कारण उनको मुख्य न्याया-धीश के आसन पर बिठाया गया। अगर हमारे मंत्री महोदय उनके बारे में सफाई दे सकें कि उनको कुछ ज्यादा अनुभव था तब तो उनका चुना जाना ठीक है, नहीं तो एक चार्ज लगाया जाता है कि प्रधान मंत्री महोदय के दरबार में हाजरी दी और जिस प्रकार एक कमिटेड जुडिशरी की बात कही जाती है, उसकी बेसिस पर कमिटेड जुडिशियरी के लिए उनको चीफ जस्टिस के पद पर लाया गया। तो श्रीमन्, इस तरह से देश में जो रही सही प्रजातंत्र की मर्यादा थी उस मर्यादा को समाप्त करने का यह सब से बड़ा कदम उठाया गया। आज देश में सचमुच में जो बुद्धि-जीवी वर्ग है, जो न्यायप्रिय है, जो न्याय को समझता है, वह आज सरकार के इस कदम से आतंकित है और वह यह समझता है कि देश में जो रहा सहा प्रजातंत्र सुरक्षित था वह भी आज चला गया। आज देश चाहता है कि अगर सच-मुच सरकार ने किसी भावावेश में इस काम को किया है तो वह इस पर पुनर्विचार करे। यदि वह इस पर पुनर्विचार कर सकती है तभी मैं समझता हूं कि इस देश में प्रजातंत्र के प्रति लोगों में विश्वास जम सकता है, अन्यथा लोग यही विचार करने के लिए बाध्य होंगे कि जिस तरह से देश में साम्यवाद बढ़ा है उसी तरह से और द्रुत गति से उस ओर देश को बढ़ाने के लिए यह अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। एक कमिटेड जुडिशियरी, एक मनचाही जुडिशियरी स्थापित करना इस देश में प्रजातंत्र को समाप्त करने का सब से बड़ा कलंकित कदम होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। आज चारों ओर अखबारों में, बड़े बड़े विचारकों के दिमाग में सब से बड़ी समस्या यही बनी हुई है और इस समस्या पर सरकार क्या बोल रही है और कोई कन्विंसिंग रिप्लाई या संतोषजनक उत्तर नहीं दे रही है। आज श्री गणेश जी सचमुच यदि कोई ऐसा इसका उत्तर दें जिस से देश को और संसद को वे अपने विश्वास में ले सकें तो वह बड़ी बात होगी, अन्यथा देश में हाहाकार मच जाएगा।

श्रीमन्, आज सभी समस्याओं का रामबाण राष्ट्रीयकरण समझा जाता है। इन्होंने कोकिंग कोल का राष्ट्रीयकरण किया। उस समय उन्होंने नान-कोकिंग कोल को छोड़ दिया था। फिर बाद में इनको लगा कि हर समस्या का निदान पूरे राष्ट्रीय-करण में होगा। इसलिए इन्होंने नानकोकिंग कोल का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। लेकिन उससे देश में एक भयंकर स्थिति पैदा हुई है। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी इस से अपरिचित नहीं होंगे कि आज हमारे देश में

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

लोगों को जलाने के लिए भी कोल नहीं मिलता है। कोल कपिटलिस्टों के उपयोग का एक साधन हो सकता है, बड़े बड़े कल कारखानों में उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो खाना पकाने के लिए कोयले का उपयोग करते हैं उनको वह क्यों नहीं प्राप्त होता है। क्या सरकार कोयला भी गरीब, मध्यम वर्ग के कंज्यूमर्स को उपलब्ध नहीं करा सकती। जो सरकार उनको कोयला उपलब्ध नहीं करा सकती उस सरकार को उसके राष्ट्रीयकरण करने का क्या अधिकार है या उस सरकार को शासन में बने रहने का क्या अधिकार है। यह सरकार न रोटी दे सकती है और न रोटी सिझाने के लिए कोयला दे सकती है। चीजों की महंगाई का कहां तक वर्णन किया जाय। आज प्रत्येक चीज की दर आसमान को छू रही है।

लोग परेशान हैं। ये गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीते, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सरकार महंगाई हटा देती, भुखमरी हटा देती तो भारत की जनता का बहुत कल्याण हो जाता। जिस समय गरीबी हटाने के लिए नारा लग रहा था उस समय बिहार के वनवासियों की स्थिति क्या थी इस को आप देखें। वह सदा गरीबी में ही रहते हैं। गरीबी में ही पैदा होते हैं, भुखमरी में पैदा होते हैं और वंशानुवंशगत गरीबी और भुखमरी में ही मर जाते हैं। उन को कभी भरपेट अनाज नहीं मिलता और कभी पूरा वस्त्र नहीं मिलता और निवास के लिए भरपूर कभी व्यवस्था नहीं हो पाती। पता नहीं ऐसे देश में आप गरीबी हटाने की बात कैसे करते हैं। मैं द्वारका का रहने वाला हूं। जब कभी वहां जमीन कट जाती है तो अच्छे अच्छे किसान की हालत भी खराब हो जाती है। गरीबी मैंने देखी है, लेकिन वहां के वनवासियों को तो देख कर सचमुच में अवाक रहने की स्थिति में हम आ जाते हैं। संथाल परगने में गत वर्ष उन लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। त्राहि माम् त्राहि माम् करते हुए वे लोग शहरों में भागकर आते रहे। तो इस देश में जहां लोग नंगे रहते हैं, भूखे रहते हैं, पानी से प्यासे रहते हैं, उस देश में गरीबी हटाने की बात यह सरकार करे और वह सरकार उन नंगे भूखों के लिए कोई व्यवस्था रोटी और कपड़े की न कर सके, सिर्फ राष्ट्रीयकरण का नारा देती रहे और उस राष्ट्रीयकरण में जो गलत बातें कोई सुझाये उन को गाली देने का काम आज हमारी प्राइम मिनिस्टर का रह गया है, उन के लिए और कोई काम बाकी नहीं बचा है, तो इससे देश का कल्याण नहीं होगा। मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप इस समस्या के निराकरण का क्या उपाय कर रहे हैं।

श्रीमन्, पेट्रोल का दाम तो बढ़ा ही, लेकिन पता नहीं सरकार ने इस बात को सोचा है या नहीं कि पेट्रोल का उपयोग केवल बड़े लोग ही नहीं करते, मध्यम वर्ग की जनता, स्कूटर चलाने वाले भी उस का उपयोग करते हैं और उन पर भी इस बढ़े हुए दामों का असर पड़ता है। आज तो देहातों में किरोसिन तेल भी उपलब्ध नहीं है जिस से कि वहां के लोग रात्रि के अंधकार से छुटकारा पा सकें। मैं अपने वित्त मंत्री महोदय का ध्यान बिहार के बरौनी तेल शोधक कारखाने की ओर ले जाना चाहता हूं। उस कारखाने को बने बरसों हो चुके हैं। और पेट्रो केमिकल कारखाने के बाई-प्रोडक्टस से 110 प्रकार के दूसरे छोटे मोटे उद्योग धंधे खड़े किये जा सकते हैं और इस प्रकार बहुत बड़ा उद्योग वहां पेट्रो-केमिकल्स का खुल सकता है। लेकिन आज तक सरकार तय नहीं कर पाती कि यह पेट्रो केमिकल कारखाने मुंगेर में कहां खुलें, कहां बनें। और अगर यह पूछा जाय कि वे कब तक बनेंगे तो इस का तो पता नहीं सरकार क्या जवाब देगी। लेकिन मैं अपने माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर आप देश का विकास करना चाहते हैं और बेकारी को मिटाना चाहते हैं तो वहां पेट्रो केमिकल्स कारखाने और उस के बाई प्रोडक्टस से बनने वाले कारखाने कब तक तैयार होंगे। उन के तैयार होने पर ही वहां की बेकारी मिट सकती है। तभी वहां के जवानों को काम मिल सकता है। लेकिन आप को किसी निर्णय को लेने में वर्षों लग जाते हैं। एक छोटा सा खाद का

कारखाना जो बहुत दिनों से बन रहा है वह भी आज तक चालू नहीं हो सका। तो किस प्रकार आप बड़ी समस्याओं का निराकरण करेंगे।

श्रीमन्, आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेकारी है और बेकारी की समस्या के बारे में पहली पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ न कुछ लेखा जोखा प्रकाशित किया जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों पंचवर्षीय योजनायें बनती गयीं वैसे वैसे बेकारों की संख्या बढ़ती गयी और आज अपने देश में लाखों इंजीनियर, हजारों डाक्टर और करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे नौजवान हैं बेकार जिन के, मां-बाप ने बड़े अरमान से उन को पढ़ाया कि वे उन के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन आज भी वे उन पर भार बने हुए हैं। श्रीमन्, आप छोटी छोटी योजनाओं की बात करते हैं उन में उन को काम दिलाने की बात करते हैं, लेकिन सरकार यह तो बताये कि आज सचमुच में देश में कितने बेकार है और उन की समस्या का निराकरण करने के लिए वित्त मंत्री जी ने कितने वित्त का आवंटन किया है और वित्त मंत्री जी को यह किस प्रकार महसूस होता है कि व देश के नौजवान के हाथ का सदुपयोग कर सकेंगे जिस के हाथ में काम करने के लिए खुजलाहट होती है, उन को वह कैसे काम दे कर उस की खुजलाहट शांत करेंगे। और ऐसा कर के वे किस प्रकार देश को समृद्धशाली बनायेंगे। यह जानने की आज देश की इच्छा है और मुझे विश्वास है कि हमारे नौजवान वित्त मंत्री जी इस ओर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और कुछ न कुछ ऐसा रास्ता सुझायेंगे जिस से कि हमारे नौजवानों को यह पता लगे कि हमारे देश में उन के लिए भी कुछ करने को है।

श्रीमन्, मैं दो शब्द सुरक्षा और शिक्षा पर कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्रीमन् हमारे पूर्ववक्ता ने सुरक्षा के बारे में ध्यान दिलाया है लेकिन मैं आपका और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज अणुशक्ति का युग है, आज प्रक्षेपास्त्रों का युग है और जब तक हम अपनी सेनाओं के हाथ में यह शक्ति नहीं देते, उनको अणुशक्ति से युक्त नहीं करते, उनके हाथ में प्रक्षेपास्त्र नहीं देते, तब तक हम दुश्मनों को देश के बाहर रखने में सक्षम नहीं हो सकते। श्रीमन् हमने देखा कि चीन हमारे साथ ही आगे बढ़ा लेकिन आज वह अणु-बम्ब का अधिकारी होने के कारण दुनिया में बड़ी शक्तियों के साथ बैठा हुआ है। जो अमेरिका उसका तिरस्कार करता था, जो उसकी शक्ति को रोकने के लिये एक अपना संगठन तैयार करता था, स्वयं उसके राष्ट्रपति उससे दोस्ती करने के लिये वहां जाते हैं। उनको वहां जाना पड़ा। तो यह उसकी शक्ति शायद अणु-बम्ब और प्रक्षेपास्त्रों के कारण है। आज पाकिस्तान बार-बार हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हम कभी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करते लेकिन वह बार-बार आक्रमण करता है और उसके आक्रमण को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि हमारी सेनाओं के हाथ में अणु-शक्ति न हो। ऐसी अणु-शक्ति किसी पर प्रहार करने के लिये नहीं लेकिन किसी के प्रहार से बचने के लिये उसकी आवश्यकता है। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारी सेना को उससे सुसज्जित किया जाय।

श्रीमन् एजुकेशन के बारे में एक शब्द ही कहना चाहता हूं। विधान के अन्तर्गत अब तक 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये थी लेकिन हम उस ओर अग्रसर नहीं हो सके हैं और खास कर के जो पिछड़े राज्य हैं वे तो इस माने में और भी पिछड़े गये हैं जैसे कि बिहार। इसलिये मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह यह बतायें कि अनिवार्य शिक्षा की ओर किस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। वह इसकी जानकारी दें।

श्रीमन्, पिछड़े वर्ग और हरिजन वनवासी छात्रों के लिये सरकार छात्रवृत्ति देती है लेकिन जहां पर पिछड़े वर्ग और हरिजन वर्ग के वनवासी छात्रों के लोगों की संख्या बढ़ी है। वहां पर उसी अनुपात से छात्रवृत्ति नहीं बढ़ी है और शिक्षा का खर्चा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन वह छात्रवृत्ति ज्यों की त्यों रही है। इसलिये

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन पिछड़े वर्ग के और हरिजन, बनवासी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति में कौन सी वृद्धि आप कर रहे हैं। जिस अनुपात में उनकी संख्या बढ़ी है उस अनुपात में आप कौन सी वृद्धी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय उनके लिये भी कुछ करें, सिर्फ नारों से ही उनका पेट न भरें।

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मैं विनियोग विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। नवल किशोर जी ने जहां इस बात का जिक्र किया . . . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : विरोध कीजियगा तब भी पास हो जायगा।

श्री रणबीर सिंह : वह तो आप करें। आपके वगैर भी पास होगा। नवल किशोर जी ने अपने भाषण को शुरु करते हुये और आखिर में कहा कि यह तो पास हो गया लेकिन वह सरकार से चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्यवाही की जाय और त्यागी जी ने बीच में कहा कि मेरा चश्मा काला है, तो एक बात मुझे समझ में आई कि दरअसल में आज देश के अन्दर देखने का दो तरीका क्यों हो गया है, एक तो आशावादी हैं और एक निराशावादी हैं और जो भाई विरोधी दलों के हैं उन्होंने निराशावाद की ओर अपना सहारा पकड़ा है। दुनिया जब से चली है तब से वह आशावाद के भरोसे पर चली है। बच्चे को पिता पालता है एक आशा ले कर कि यह बड़ा हो कर मुझे कमा कर खिलायेगा। लेकिन हिन्दुस्तान के विरोधी दल हैं कि सब कुछ उन्हें ऐसा मालूम देता है कि इस देश के अन्दर कोई तरक्की ही नहीं हुई है। श्रीमन्, आपको याद होगा कि हिन्दुस्तान की पहली पंचशाला योजना जब बनी तो वह 1800 करोड़ रुपये की थी, वह पांच साल की थी, और अभी वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि 1973-74 साल के अन्दर हम योजना के ऊपर कितना खर्च करने जा रहे हैं। वह 1800 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। जो पांच साल के लिये था उससे भी कहीं ज्यादा है। मैं मान सकता हूं कि रुपये की कीमत गिर गई है। लेकिन क्या इस अनुपात से करें कि वह जो 5 साल में हम खर्च करते थे, आज एक साल में खर्च करने जा रहे हैं। उसका कोई तनासुब है क्या इतना गिर गया कि वह उससे भी कम हो गया।

उपसभाध्यक्ष जी, जब देश आजाद हुआ उस वक्त इस देश की बिजली पैदा करने की क्षमता 20 लाख किलोवाट थी और अब वह क्षमता 175 लाख किलोवाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की हो गई। तो क्या बिजली वैसे ही पैदा होती है? उसके लिए कोई बिजली घर लगे या नहीं लगे, कोई तरक्की देश की हुई या नहीं हुई? आज देश के चप्पे-चप्पे में जो हो रहा है वह इस बात की शाहिद है कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे विरोधी दलों को सिवाय निराशावाद के कोई और बात नहीं दिखायी देती तो इसमें हमारा कसूर नहीं हो सकता है। अगर आपका सहारा ही निराशावाद है तो नतीजा उसका अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है, हार खा कर आदमी कई दफा घबरा जाता है, हो सकता है हारने की वजह से निराशावाद की तरफ उनका ध्यान चला गया हो लेकिन उसमें तो कोई मुक्ति होने वाली नहीं है। आशा रख कर ही आदमी आगे बढ़ सकता है।

उपसभाध्यक्ष जी, मुझे याद है--और त्यागी जी को भी याद होगा--कि पहला पहला बजट 1948-49 का कोई 700-800 करोड़ रुपये साल था। अब कितने हजार करोड़ रुपये का है? इससे देश की क्षमता बढ़ी, शक्ति बढ़ी, देश आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा? बजट के आंकड़े ही बता सकते हैं---1948-49 के बजट आंकड़ें अगर आप देखें--कि देश की रक्षा के लिए कुल 250 करोड़ रु० रखे थे, और आज 1600 करोड़ रुपये देश की रक्षा के लिए रखे हैं। देश की और तरक्की की बात जाने दीजिए, क्योंकि अभी रक्षा के बारे में बड़ी चिन्ता थी और यह ठीक ही है कि हर भाई को देश की रक्षा की चिंता है और करनी चाहिए और इस बात की चौकसी भी करनी चाहिए कि देश के जो कार्यकर्त्ता हैं, काम

करने वाले है, वे भी हौसले से पैर बढ़ा कर आगे बढ़ें। निराशा से काम नहीं चलता।

उपसभाध्यक्ष जी, जिक्र किया गया अनाज के व्यापार के राष्ट्रीयकरण का, गेहूं के भाव तय करने का। मैं नवल किशोर जी से इस बात में सहमत हो सकता हूं कि गेहूं का भाव जो मुकर्रर किया गया, वह ठीक नहीं हुआ। मैं ही नहीं हिन्दुस्तान के कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं कि वह जो भाव मुकर्रर हुआ, कोई ठीक नहीं हुआ। नीची दर मुकर्रर हुई। लेकिन इसके साथ साथ, क्या हिन्दुस्तान के किसान इस बात को भूल सकते हैं कि पच्चीस साल की हमारी आजादी के बाद और हिन्दुस्तान जब से चला आया, तब से लेकर आज तक, यह साल पहला साल है, जब किसान की पैदावार का भाव मुकर्रर हुआ और पहले जब किसान अनाज पैदा करके गाड़ी में लेकर आता था तब किसान को अलाहिदा बैठा दिया जाता था और फिर उसके अनाज की बोली होती थी, नीलामी होती थी, जैसे वह मुर्दे आदमी का सामान हो। उसको कोई हक नहीं था और व्यापारी दूर बैठे-बैठे सपके हथेली दबा कर भाव मुकर्रर करता था। मैं मानता हूं भाव गेहूं का ठीक नहीं है, लेकिन यह बात बहुत सही है कि किसान जो अपनी मेहनत से पैदा करता है, उसकी नीलामी तो नहीं होती है। आज तक उसके सामान की नीलामी होती थी। असली बात क्या है? यह एक साजिश थी। हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री ने और हिन्दुस्तान की सरकार ने पहली दफा हिन्दुस्तान के इतिहास के अंदर किसान जो पैदावारी करता है, उसकी सरकारी तौर पर कीमत मुकर्रर करने का फैसला किया और उस कीमत के ऊपर खरीददारी सरकार खुद ही करेगी। कीमतें तो पहले भी मुकर्रर हुई, लेकिन सरकार ही खरीदेगी गेहूं को, यह पहली दफा सरकार ने फैसला किया और उसका श्रेय हिन्दुस्तान की कांग्रेस और प्रधान मंत्री को न मिले?

इसलिए यह एक बहुत बड़ी साजिश है जिसकी वजह से आज हिन्दुस्तान के किसानों को बहकाया जा रहा है। पहले किसानों के सामान की हिन्दुस्तान की मण्डियों में नीलामी होती थी, हिन्दुस्तान के कोने-कोने में उसकी चीज की नीलामी होती थी। हिन्दुस्तान की हर मण्डी में, हिन्दुस्तान के किसान की मेहनत और पसीने से तैयार की गई पैदावार की नीलामी होती थी, जैसे कि वह कर्जदार हो और उसके पास कोई साधन नहीं है कि किस तरह से कर्जा अदा किया जाये और इसी वजह से उसकी उपज की नीलामी की जाती थी। अब सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कदम उठाया है, उसकी वजह से अब आगे के लिए उसकी फसल की नीलामी नहीं हो सकेगी।

श्री नवल किशोर जी ने चने और दालों के भावों का जिक्र किया। मैं इस बात का मशकूर हूं कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन मैं उन्हें यह बतलाना चाहता हूं कि अगर आज किसान को गेहूं के कुछ कम दाम मिल रहे हैं, तो वह फिर चने से और दालों की पैदावार को ज्यादा करके पूरा कर सकता है। अब यह सवाल किया जा सकता है कि अगर इस मौसम में किसान को गेहूं के दाम कम मिले, तो अगले मौसम में गेहूं की पैदावार कम हो जायेगी। यह बात सही है, जिस जमीन में, जिन हालात में गेहूं की फसल पैदा होती है, उन हालात में दूसरी फसल पैदा नहीं की जा सकती है। गेहूं पैदा करने के लिए खास मौसम चाहिये, पानी चाहिए और जमीन की ठीक हालत होनी चाहिये। चना तो कम वर्षा में भी हो सकता है और दाल भी कम पानी की वजह से पैदा हो सकती है। असल बात यह है कि आगे चल कर इस बात का क्या असर पड़ने वाला है। यह बात इस बात पर निर्भर करेगी कि अगली फसल के लिए भाव क्या मुकर्रर किये जाते हैं। गेहूं और चावल के भाव एक साल पहले तय कर लिये जायेंगे। आज जिस भाव में किसान को गेहूं बेचना पड़ रहा है, वह एक साल पहले तय हो चुके थे और भविष्य में जो भाव तय होंगे, उसके लिए किसान को बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान काफी समझदार हो गया है। लेकिन आज किसानों से यह कहा जाता है कि वह अपना अनाज मंडियों

[श्री रणवीर सिंह]

में न ले जायें। किस लिए यह बात कही जाती है ? इसलिए कही जाती है कि जब वर्षा का मौसम शुरू हो जायेगा, रेलों में लदान नहीं हो सकेगा, गोदाम जो हैं, वे भर जायेंगे, तो फिर यह व्यापारी लोग जिस तरह से इन्होंने पिछले साल सस्ते भाव में गल्ला किसानों का खरीदा था, उसी तरह से इस साल भी उनका गल्ला सस्ते भाव में खरीदेंगे और यही वजह है कि वह किसानों से कह रहे हैं कि गल्ला मंडियों में न ले जायें। इस तरह की बात एक-दो साल पहले हो चुकी है, जब कि स्कूल अनाजों से भर चुके थे और लदान बन्द हो गया था, तो किसानों को अपना अनाज सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज व्यापारी उसी तरह की हालत करना चाहते हैं ताकि वे सस्ते भाव पर अनाज खरीद सकें, लेकिन अब किसान काफी जागरूक हो गया है और वह समझ गया है कि किस तरह से उसकी मेहनत द्वारा चीज को बेचा जा सकता है। आज हमारे भाई किसानों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन यह तो एक साजिश है और हमदर्दी की बात उसमें नहीं है। जब गेहूं के भाव सात-आठ महीने पहले तय किये गये थे, तो उस समय ये भाई कहां थे, जो आज गेहूं के दाम बढ़ाने की बात कह रहे हैं। उस समय उन्होंने गेहूं के दाम बढ़ाने की बात क्यों नहीं की और क्यों नहीं उस समय किसानों के साथ हमदर्दी दिखलाई। इससे यह साफ जाहिर होता है कि आज वे जो बात कह रहे हैं, वह किसान के हित की आवाज नहीं है, बल्कि वे तो हिन्दुस्तान के किसान के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं तथा उनकी एक झूठी हमदर्दी लेकर उनके हितों के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की जा रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि हमारे देश में जो चीनी के कारखाने है, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। हमारे मित्र बहुत-सी चीजों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, लेकिन जब किसी चीज का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो फिर उस चीज की बुराई करते हैं कि आज जनता को कोयला नहीं मिल रहा है। अभी कोयले का राष्ट्रीयकरण किये हुए बहुत कम समय हुआ है, छः महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, अभी तो यह एक तरह से बच्चा है। जिस तरह से पांच, छः महीने के बच्चे की हर तरह से देखभाल करनी पड़ती है, उसी तरह से कोयले के कारखानों की भी हर तरह से देखभाल हो रही है और कुछ समय के बाद जितनी भी मुश्किलात अभी आ रही हैं, वे दूर हो जायेंगी। इन चीजों के लिए समय चाहिये और जो उसमें पहले से खराबी है, उस खराबी को दूर करने के लिए समय चाहिये। दवा भी अगर किसी मरीज को दी जाये तो कुछ दिनों देने के बाद ही या कुछ वक्त के बाद ही उसका असर होता है और इस चीज में वक्त लगता है।

शायद त्यागी जी को याद होगा कि जिस समय यहां पर लोहे के कारखाने लगाये जा रहे थे तो श्री मुकर्जी, जो टिस्को के चेयरमैन थे, इस समय मुझे अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा है, उन्होंने यह गवाही दी थी कि इस देश में लोहे की कोई खपत नहीं है और बाहर दुनिया में लोहा बिक नहीं सकता, जो लोहा पैदा होगा वह महंगा पड़ेगा। लेकिन आज हालत यह है कि लोहे की हमारे देश में बहुत कमी हो गई है। एक तरफ तो हम कहते हैं, कि उपभोक्ताओं को अनाज नहीं मिलता है।

फेयर प्राइस शाप्स पर अनाज नहीं है और दूसरी तरफ किसानों से कहते हैं, अनाज न लाओ। तो क्या आसमान से अनाज आएगा। इस देश के लोगों से खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है।

फिर कहते हैं कि इस देश के अन्दर सबसे ज्यादा समझ की ठेकेदारी प्राइम मिनिस्टर ने ली है। तो समझदार क्या आपको मानें जो एक तरफ किसानों को कहते हैं कि अनाज न लाओ और उपभोक्ता को कहते हैं कि अनाज लो, चोर को कहें कि लग जाओ और शाह को कहें कि जाग जाओ, दोनों की लड़ाई होगी तो शायद कुछ मिल जाये। यह नीति देश की भलाई की नहीं है। सहयोग चाहिये, लेकिन क्या यह सहयोग देने का तरीका है। अगर विरोधी पार्टियां इसी तरह से सहयोग देना चाहती हैं, तो आप दें या न दें, लोग सहयोग देंगे, क्योंकि लोगों के लिए सरकार चलती है। कितना ही आप गुमराह करने की कोशिश करें, हिन्दुस्तान के मतदाता काफी समझदार हैं, हमसे भी ज्यादा समझदार हैं। आप भले ही मानें

कि हम समझ के ठेकेदार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के मतदाता हम सबसे ज्यादा समझदार हैं।

कहते हैं कि प्रधान मंत्री डिक्टेटर बनने जा रही हैं । इस देश के अन्दर मताधिकार 22-23 करोड़ को मिला हुआ है । जनता ने किसी को जिताया, किसी को हराया । हमारी पार्टी के भी कुछ भाई हारे, दूसरी पार्टियों के भी हारे । फिर आप कैसे मान लेते हैं कि हम ही प्रजातंत्र के ठेकेदार हैं ।

आज बड़ी दुहाई दी जाती है कि जजों की जिनकी सीनियोरिटी तोड़ कर चीफ जस्टिस बना दिए गए हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के । वह जज जब सीनियोरिटी तोड़ कर आए तब उनको पता नहीं चला कि सीनियोरिटी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। जब उनकी खुद की तरक्की हो रही थी तो सीनियोरिटी तोड़ना अच्छी बात थी, अगर दूसरे की तरक्की हो जाये, तो वह बुरी बात है । विधि आयोग ने 15 साल पहले सिफारिश की थी, दूसरे आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, उसी के ऊपर कार्यवाही होगी, चाहे वह 15 साल के बाद हो, 4 साल के बाद हो या 2 साल के बाद हो। अगर वे कहते कि कार्यवाही करने में 15 साल की देरी की तो मेरी समझ में आ सकता था, लेकिन समय की वजह से उस बात का मूल्य तो नहीं बदल जाता। इस बात को क्या इस देश के अन्दर कोई जानता नहीं है कि इस देश के लाखों गरीब आदमियों को किस तरह न्याय मिलता है ? हिन्दुस्तान के बहुत सारे वकील आज दुहाई दे रहे हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर प्रजातंत्र खतरे में है। कौन हैं ये भाई? ये वही हैं जो गरीबों से पैसा लेते हैं, गरीबों से पैसा लेकर वकालत करते हैं और गरीबों को लूटते हैं, ये वे भाई हैं जो देश के अगुआ बनना चाहते हैं। वह जमाना बीत गया जब हिन्दुस्तान के अन्दर वकील ही नेता हुआ करते थे और लोग वकीलों की बात सुन कर चला करते थे । जो लोग वकील हैं, राजनीति में हैं, इस सदन में हैं, वे ज्यादा दिन प्रजातंत्र में टिक नहीं सकते ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा (मध्य प्रदेश) : आप कह रहे हैं कि वकील पैसा लेकर पैरवी करते हैं तो क्या आप मजदूरों को अनाज दे रहे हैं, बिना पैसे के ?

श्री रणवीर सिंह : सखलेचा साहब, मालूम होता है, खुद वकील हैं, उनको चोट लगी है। कौन वकील हैं जो सही इनकम टैक्स पे कर रहें हैं । जज फैसला देता है, किसी की पिटीशन मंजूर हो जाय, रिजेक्ट, हो जाये, वकील चार-पांच हजार रुपया ले लेता है लेकिन वह दिखाता कितना है चार सौ। वह वकील दयानतदार है, ईमानदार है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जो भाई अगुआ बन रहे हैं, व इस देश की आम जनता के हमदर्द नहीं हैं । यह सही बात है कि गरीबों को आज न्याय महंगा है और इस तरीके से न्याय सस्ता करना होगा और यह जो ठेकेदारी थी, इसे खत्म करना होगा। विधान बदला था किसके लिए ? हिन्दुस्तान के गरीबों के लिए, वह अकेली कांग्रेस पार्टी ने नहीं बदला। 15 जज थे, कितने ही अच्छे हों, कितने ही समझदार हों, वह इस बात को नहीं देखते कि हिन्दुस्तान के अन्दर चुनाव हुए, 34 करोड़ लोगों ने मत डाले, खुले आम और उसके ऊपर भी वह फैसला देने वाले हैं ? जिनकी समझ का दिवाला निकल गया तो वह देश को कहां ले जाने वाले हैं । चाहे वह जज हैं या दूसरे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिये जो भी रोड़ा हो उसको हटाना होगा। हमको भी लोग कल हटायेंगे और जज हों तो उनको भी हटायेंगे । जो चीफ जस्टिस बने, वह भी जज हैं, काफी तजुर्बेकार हैं। किसी जज को ही चीफ जस्टिस बनाया गया है, किसी कांग्रेस पार्टी के मेम्बर को तो नहीं बनाया है, चीफ जस्टिस । इसके लिए आपत्ति क्या है ? इसमें क्या आपत्ति आ गई, कौन-सी आपत्ति है ? बात साफ है कि इस देश के अन्दर कुछ जज तो यह समझते थे कि उनकी ठेकेदारी है समझ की, और जो कांस्टीट्युयेंट एसेम्बली या पार्लियामेंट फैसला करे, देश की 24 करोड़ जनता मताधिकार से फैसला करती है, उसको भी रद्द करने की जो कोशिश है, वह चलेगी नहीं । असल में कोई चोट है, तो वह है । उसके लिए हम विधान भी बदल सकते हैं । त्यागी जी और हम विधान बनाने वालों में से थे, उस समय हम देवता थे और आज हम राक्षस हो गये ? उस समय भी एम० एल०एज० ने हमें चुन कर भेजा था और आज भी आप

[श्री रणवीर सिंह]

को भेजा है ।

आज हमारे पीछे कौन-सी पुछ है, जो गायब हो गई । तो यह बात समझने की है । देश की जब तरक्की होनी है, जब देश आगे जा रहा है, उसके मुताबिक अगर कोई उसको पीछे हटाने की कोशिश करेगा, पीछे खींचेगा तो चाहे वह कितना ही समझदार हो, कितना ही कानूनदां हो, कितना ही बोलने में अच्छा हो, हिन्दुस्तान की जनता जिसको मताधिकार मिला हुआ है, वह बोलना नहीं जानती, लेकिन अपने अख्तियार का ठीक तरह से इस्तेमाल करना जानती है । हिन्दुस्तान के अन्दर न कोई डिक्टेटर बनना चाहता है, न कोई बन सकता है । त्यागी जी जब इधर बैठते थे उस वक्त क्या हालत थी और आज क्या हालत है । और जो तरक्की हुई आज, उसको वह न मानने लगे; क्योंकि वह दो साल से उधर बैठने लगे हैं, वह माने कि कोई तरक्की नहीं हुई है, तो यह ठीक नहीं है । कोई भाई विरोधी दल का हो या हमारी पार्टी का, यदि यह कहे कि तरक्की की रफ्तार सुस्त है, तेज होनी चाहिए, वह हम मानते है । मैं त्यागी जी से सहमत नहीं हूं कि पैसे के प्रसार से बड़ा नुकसान हो जाता है । अगर पैसे के प्रसार से कोई महंगाई होती तो वह महंगाई पंजाब में होनी चाहिए थी, वह हरियाणा में होनी चाहिए थी । सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में पैसे का प्रसार बढ़ा है, तो वह पंजाब और हरियाणा में बढ़ा है और वहां भाव सबसे कम हैं । तो पैसे के प्रसार से महंगाई का ज्यादा कोई सम्बन्ध नहीं है । देश में चीजों की पैदावार से भी उसका सम्बन्ध है और मैं जानता हूं कि अगर हमारा तरीका मर्केंटाइल इकानामी का हो, सोशलिस्ट समाज बनाने के लिए हमारी सोच मर्केंटाइल इकानामी की हो, तो वह बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है । हमारी सोच बहुत दिन तक कायम है, उसको हमें अब बदलना है । रुपया पहले छापते थे गोल्ड सेक्यूरिटी पर । मैं कहता हूं कि भाखड़ा डैम की सेक्यूरिटी पर छापना सबसे बढ़िया है । भाखड़ा डैम देश को अर्पण करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू गये थे, उस समय में पंजाब का पानी और बिजली, का मंत्री था । उस वक्त मैंने कहा था कि आज भी सरकार की रुपया छापने की जो नीति है, वह बदलनी चाहिए । उस डैम को कोई चुरा करके ले नहीं जा सकता । अंग्रेज भी इस बात को मानता था कि खेती के पैदावार के लिए नहरों का प्रसार करना, खाली रुपये के हिसाब से नहीं देखना होगा । पंजाब के अन्दर, हरियाणा के अन्दर भाखड़ा डैम बना । भाखड़ा डैम का अलाहदा से हिसाब देखा जाये तो उसकी जो सीधी आमदनी है, उस सीधी आमदनी से खर्चा पूरा आज भी नहीं होता । लेकिन इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि भाखड़ा डैम के पानी से पैदावार बढ़ने के कारण अकेले हरियाणा में 20 करोड़ रुपये साल का सैल्स टैक्स बढ़ा है । अगर पानी मिलेगा तो उससे खेती की पैदावार बढ़ेगी । अगर सड़कें बनेंगी तो उससे देश की तरक्की होगी । मैं तो कहता हूं कि देश के अन्दर जितनी भी जगह पानी की योजनाएं हैं, उनको चलाने के लिए जितने रुपये की भी जरूरत हो उसको खर्च करना चाहिये । एक तरफ आज इंजीनियर बेकार है, दूसरी तरफ मजदूर बेकार है और तीसरी तरफ हमको पानी नहीं मिल रहा है, हमको पानी की जरूरत है । आज पता नहीं हमारा कितना पानी बेकार चला जाता है, पाकिस्तान चला जाता है । रावी का पानी हमने करोड़ हा रुपया देकर के खरीदा है, लेकिन उसके ऊपर हम डैम बनाना शुरू नहीं करते । इसी तरह से आज आप देखिये कि दिल्ली पानी से डूब जाती है । मैंने डा० राव से कल बताया था कि जिस वक्त कि साहू डैम बन जायेगा तो दिल्ली में अभी जमुना जितने इलाके में बहती है, उसके बजाये उसके लिए बहुत कम इलाके की जरूरत रह जायेगी । फिर बाकी जो जमीन बचेगी उसमें मकान बन सकते है और वह जमीन करोड़हा रुपये की बिकेगी । उससे उसका घाटा निकल जायेगा । इसलिये मैं कहता हूं कि चाहे कि साहू डैम हो, चाहे थायी डैम हो, चाहे कोई और डैम हो, उन सब को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिये ताकि देश आगे बढ़ सके ।

[श्री रणबीर सिंह]

आज केन्द्रीयकरण की बहुत बात की जाती है । मुझे याद है कि यहां पर दिल्ली में एक ट्रेन खुद रहा था, जिसके खोदने वाले हिन्दुस्तान की सरकार के बड़े-बड़े विशेषज्ञ और इंजीनियर थे, लेकिन सात वर्ष में कोई काम नहीं हुआ । एक बार डा० राव ने मुझसे कहा था कि पंजाब के इंजीनियर इसको खोद सकते हैं । हमारे बड़े-बड़े इंजीनियर हैं जो उतनी तेजी से काम नहीं करते हैं, जितनी तेजी से कुछ प्रदेशों के इंजीनियर और आफिसर काम करते हैं । जिन प्रदेशों में इंजीनियर तेजी से काम करते हैं, उनमें तामिल नाडु है, पंजाब है, हरियाणा है। तो बजाये इसके कि हम इस बात को देखें कि इस देश के अन्दर में, हरियाणा में, इतनी जल्दी बिजली का प्रसार कैसे हो गया, हिन्दुस्तान के विरोधी दलों को यह फिक्र है कि क्या गलती कर दी । उसमें कितना नुकसान हुआ । यही देखिये । मैं तो चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय कोई समिति बनाये और वह देखे कि देश के अंदर जो बिजली पैदा होती है उसकी कहां क्या कास्ट पड़ती है । हमारा उत्तर प्रदेश है। हमारे और उसके बीच में यमुना नदी है। उसके परले पार गन्ना जितना होता है उस के ऊपर आबयाना हरियाणा के मुकाबिले में इधर दुगना होता है । ट्यूबवेल का भी आप यही हिसाब देखेंगे । तो आखिर इसका क्या कारण है, जो प्रोजेक्ट बनते हैं, उनको जिस कीमत पर हम बनाते हैं, उसकी बड़ी चर्चा होती है। इस बात की बड़ी चर्चा रही कि हरियाणा के एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काफी लूट मची । लेकिन हरियाणा के एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जिस कीमत पर जितना प्रसार किया है, उसके अनुपात से किसी दूसरे प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ और अगर कहीं हुआ है तो उससे हम सीखेंगे तो इसलिए हमारे देश के अंदर हमको कोशिश करनी चाहिए कि जहां-जहां तरक्की हुई है, उससे हम कुछ सीखें । मैं मानता हूं कि तमिल नाडु में काफी तरक्की हुई है और तमिल नाडु से काफी शिक्षा दूसरे प्रदेश ले सकते हैं । हरियाणा के स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हिन्दुस्तान के दूसरे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काफी शिक्षा ले सकते हैं । तो बजाये इसके कि हम इस तरफ जायें, हम एक दूसरे में त्रुटि निकालते रहते है । मैं यह नहीं कहता कि अगर कहीं कोई त्रुटि है तो वह सरकार को न बतायी जाये । उसे बताया जाना चाहिये और उसको ठीक किया जाना चाहिए, उसको हटाना चाहिये, लेकिन हम सिर्फ त्रुटियां ही देखें और काला चश्मा लगा कर सारी स्याही ही स्याही देखते रहें और किसी चीज में अगर कोई अच्छाई हो, तो उसको न देखें, इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता और ऐसा करने से देश की तरक्की नहीं हो सकती ।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, यह जो विनियोग विधेयक आया है इसमें जो प्राविधान हैं, उनमें देखना यह है कि हमारे सामने जो समस्यायें हैं उनका हल इस विनियोग विधेयक से कहां तक हो पाता है । आज इस बात में कोई दो मत नहीं हैं कि देश में महंगाई बढ़ी है और देश में बेकारी बढ़ रही है और अमीरी और गरीबी के बीच की खाई चौड़ी होती चली जा रही है और इस देश के करीब 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी कि रेखा है, उससे नीचे रह रहे हैं । लेकिन जब हम इन सवालों के हल की ओर देखते हैं तो उस सिलसिले में इस विनियोग विधेयक को देख कर हमें निराशा होती है और उस दिशा में यह विनियोग विधेयक अपने आप में असफल साबित होता है । मैं एक सवाल को इस संबंध में लेना चाहूंगा । सरकार की यह घोषित नीति है कि वह गरीबों और अमीरों के बीच की जो खाई है, उसको वह कम करेगी । इसके लिए एक आम नारा भी देश में लगा और आज भी लगता है कि गरीबी को मिटाया जायेगा । इसका दूसरा अर्थ यह निकलता है कि देश में जो कुछ मुट्ठी भर अमीर लोग है उनकी अमीरी पर रोक लगायी जाएगी । लेकिन यह जो विनियोग विधेयक है उससे लगता यह है कि सरकार ने यह ठान रखा है कि देश में जो एकाधिकारी पूंजीपति-वर्ग है, उसको वह बढ़ावा देगी। अभी कुछ दिन पहले इस दिशा में एक प्रश्न पूछा गया था और उसमें सरकार की ओर से यह जवाब मिला था कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो एकाधिकारी पूंजीपतिवर्ग है, वह दस प्रतिशत के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है और यह जो एकाधिकार पूंजीवाद है यह कोई अपनी ताकत से

[श्री सूरज प्रसाद]

नहीं बढ़ रहा है। सब से बड़ा ताज्जुब और आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकार के जो फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन्स है, जो बैंक्स हैं, जो बीमा कम्पनियां है, जो विदेशी कारपोरेशन्स हैं वे उनको काफी मात्रा में पूंजी देते हैं और उस के जरिये वह अपनी पूंजी देश में बढ़ा रहे है और उनकी बेतहाशा वृद्धि होती चली जा रही है। मैं अपनी बात नहीं कहता क्योंकि एकोनामिक टाइम्स हम लोगों का अखबार नहीं है। उसका कहना यह है कि गत तीन, चार वर्षों में यह जो एकाधिकारी पूंजीवादियों का, पूंजीपतियों का वर्ग है वह देश के अंदर नये कारखानों में कोई अपनी पूंजी नहीं लगाता। उसको अपने कारखानों से जो मुनाफा होता है उसको वह इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि उसको वह खर्च करता है इंवेंटरी बढ़ाने में, वह उसको खर्च करता है सरकार को कर्ज देने में और रा मैटीरियल जमा करने में। उसको कोई नया कारखाना खोलने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो टेंडेंसी है एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग की यह कहां तक ठीक है और क्या इसको रोकने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं। यह भी ठीक है कि यह जो एकाधिकार पूंजीपति वर्ग है, यह देश की तमाम बीमारियों की जड़ है। मंहगाई के सवाल को लिया जाए। गत वर्ष मंहगाई 15 प्रतिशत बढ़ी यह सरकारी आंकड़ों से प्रकट होता है और इस साल भी यह मंहगाई बढ़ती चली जा रही है। सरकार का कहना यह है कि मंहगाई के बढ़ने का प्रधान कारण यह है कि गत साल देश के अंदर सूखा रहा है। और इस साल मंहगाई बढ़

4 P.M. गई लेकिन यही प्रिमाइसस करेक्ट है अगर यही बात सही है, तो हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि दालडा पर, वनस्पति घी पर, तो कोई अकाल नहीं पड़ा है लेकिन वह कोई दो तीन महीने पहले 98 रुपये टिन बिकता था और आज बाजार के अन्दर 130 रुपये टिन बिकता है। इसी प्रकार से कपड़े का प्रश्न है। गत साल देश के अन्दर में रुई का कोई बेजा प्रोडक्शन नहीं हुआ है बल्कि रुई की पैदावार दूसरी सालों से अच्छी रही है, फिर भी कपड़े का दाम इस साल बेतहाशा बढ़ा है। मैं कोई अपनी बात नहीं कहता हूं, मैं फिर "एकोनामिक टाइम्स", को कोट करता हूं, उसमें यह बात प्रकट की गई है कि हिन्दुस्तान में जितने भी कपड़े के होलसेल ट्रेडर्स है उन्होंने सभा कर के इस बात की मांग की है कि दीपावली के समय जो कपड़े का मूल्य था उसी मूल्य पर हिन्दुस्तान में कपड़ा बेचा जाना चाहिए। यह समाचार "एकानामिक टाइम्स" में जो कि डालमिया का अखबार है उसमें प्रकाशित हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि कपड़े की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है और जो मरचैन्टस है उनको डर यह है कि हो सकता है कि जिस तरह से सरकार ने अन्न के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लिया है उसी तरह से कपड़े के व्यापार को भी न ले ले और इस डर से उन्होंने यह बात करने को कहा है, उन्होंने इस तरह की बात को प्रकट करने की कोशिश की है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कपड़े के मूल्य में बेतहाशा देश के अन्दर में वृद्धि हुई है। इसलिए मंहगाई के बारे में यह कहना कि यह सिर्फ सूखे की वजह से हुई है या बगला देश की वजह से हुई है यह बात गलत हो जाती है। सबसे बड़ा कारण यह है कि कपड़ा, तेल, साबुन, जितनी भी आवश्यकता की चीजें हैं इनका व्यापार कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केन्द्रित हो गया है और ये लोग मनमाने ढंग से प्राइसेज को मैनुपुलेट करते हैं और चीजों की कीमतों को बढ़ा देते है और हम लोगों को लूट लेते है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इनको रोका जाय। हम देखते है कि इस चीज को रोकने के लिए इस बजट में कोई चीज है नहीं, इसमें कोई खास बात हमें इस तरह की नजर नहीं आती है बजट को पेश हुए करीब करीब दो महीने बीत रहे है और इस बीच में मंहगाई पर रोक लगने वाली कोई चीज नजर नहीं आती है बल्कि वह और बढ़ती ही चली जा रही है। सरकार ने टैक्स बढ़ाया और यह कहा कि इससे कोई खास प्राइस पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन ठीक इसके विपरीत बात हम लोगों को बाजार में देखने को मिलती है। आवश्यकता की जितनी भी चीजें है उनकी कीमतें रोज व रोज बढ़ती चली जा रही है। इसलिए इसका निदान यही है कि ये जो 75 एकाधिकारी पूंजीपतियों के हाउसेज है जो कि तमाम बुराइयों के केन्द्र है, जड़ है, उनको रोका जाय, जब तक हिन्दुस्तान की एकानामी पर ये हावी रहेंगे तब तक मंहगाई पर रोक लगाने की बात सोचना सरासर गलत है

समाजवाद की बात कही जाती है और दूसरे नाम भी लिये जा सकते हैं लेकिन जब तक यह बने हुए हैं तब तक मंहगाई में और कठिनाई में किसी भी तरह की कोई कमी नजर नहीं आने वाली है। ये मंहगाई के कारण हैं, ये देश में भ्रष्टाचार के कारण हैं, ये राजनैतिक भ्रष्टाचार के भी कारण हैं, देश के अन्दर जो भी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनको नष्ट करने के ये प्रधान कारण है और देश में जनतंत्र को इनसे बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी हालत में इन लोगों को खर्व करने की तरफ या इनको खत्म करने की तरफ सरकार का जो भी कदम है वह बिल्कुल ही नाकाफी है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि देश के अन्दर में जो मंहगाई है, देश के अन्दर में जो गरीबी है इसको मिटाने की कोई बात नहीं हो सकती है जब तक कि ये हैं। सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि नहीं नहीं, हम लोग तो इसकी तरफ कदम उठा रहे हैं और कदम क्या है! कहा जायगा कि हमने तो कोयले का राष्ट्रीयकरण कर लिया, हमने खेतरी में कापर उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया, हमने आम बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर लिया और इसी तरह कुछ और बातों की गिनती की जा सकती है। लेकिन यह तो नाकाफी कदम है, यह किश्त में काम करने का ढंग है। इससे कोई खास नतीजा निकलता नहीं है। आप देखिए, कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोयले के राष्ट्रीयकरण को फल यह निकलना चाहिए था कि लोगों को सस्ती दर पर कोयला मिल जाय लेकिन ठीक उसके उल्टे बात हो रही है कि जो कोयला पहले पांच-छः रुपए मन बिकता था उससे पहले 4 रु० मन बिकता था, वह अब 9 रु० 12 रु० मन बिकता है और आम लोगों को इससे परेशानी है। इससे लगता है कि राष्ट्रीयकरण के प्रति जो आम लोगों की अभिरुचि बढ़नी चाहिए थी वह कम हो गई है। सरकार एक चीज को छूती है और दूसरी चीजों को छूने में उसे डर लगता है। दूसरी चीजों को लेने का जहां तक प्रश्न है वह उनको लेने से कतरने लगती है। इसलिए किश्त में काम करने से, इन्सटालमेंट में काम करने से इस समस्या का हल निकालना असम्भव है।

मैं समझता हूं, गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने का जो प्रश्न है उसकी तरफ पहला कदम जो उठना चाहिए था वह यह था कि सरकार एकाधिकारी जो पूंजीवादी व्यवसाय है उसके एक-मुश्त राष्ट्रीयकरण की तरफ कदम उठाये। अभी आपने देखा कि चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के संबंध में एक कमेटी बहाल की गई थी लेकिन जो रिपोर्ट निकली है उसमें काफी मतभेद हो गया है। चीनी की क्या हालत है? हमको मालूम है, चीनी उद्योगपतियों के कारनामे भी हमको मालूम हैं, कि वे किसानों को उनके ईख का पैसा नहीं देते हैं। सरकार ने चीनी के उत्पादन का 70 परसैन्ट अपने हाथों में ले लिया है 30 परसैन्ट उनके हाथों में छोड़ दिया है और वह 30 परसेन्ट बाजार में 4 रु० किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है और इस तरह से हिन्दुस्तान के जो मुट्ठी भर चीनी के मिल मालिक हैं जिनकी संख्या 200 के लगभग है, उसमें 60 या 70 परसैन्ट प्राइवेट सैक्टर के शुगर केन मिल आनर्स हैं। ये लोग हिन्दुस्तान की आम जनता को करीब गत एक साल के अंदर 4 अरब रुपए तक लूट लिए हैं और उनके हाथ में उद्योग छोड़ने की बात में मतभेद हो गया। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सचमुच में अगर आप चाहते हैं कि चीनी के जो दो भाव बाजार में हैं —4 रु० और 2रु० किलो—इसको कम करना है तो इसका केवल एक रास्ता है कि हिन्दुस्तान के जो चीनी उद्योग हैं उनको अपने हाथ में ले लीजिए, इसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है और अगर यह कदम उठाया जाए तो हिन्दुस्तान का एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग जिसके हाथ में देश की दौलत सिमट गई है, उनके हाथों से वह पूंजी ले ली जाए तो यह बहुत सी बीमारियां दूर करने में मदद कर सकती है, अमीर और गरीब की खाई को मिटाने के प्रश्न को भी सुलझा सकती है, मंहगाई का जो प्रश्न है उसको भी सुलझा सकती है, और जो बेकारी का प्रश्न है उसको दूर करने की तरफ कदम उठा सकती है। इसी प्रकार अंधाधुंध जो जनता पर टैक्स लगाने का सिलसिला है उसमें भी कमी हो सकती है। इस ओर सरकार ने 2 करोड़ रु० आम लोगों पर बढ़ा दिया है। इससे न हम गरीबी दूर कर पा रहे हैं और न उसमें कमी कर पा रहे हैं। इसके अलावा नेप्था पर, लोहे पर जो टैक्स बढ़ा है उसका असर किसानों पर पड़ने जा रहा है क्योंकि नेप्था से फर्टिलाइजर तैयार होता है, नेप्था पर टैक्स बढ़ाने का मतलब यह है कि फर्टिलाइजर में मंहगाई होगी, लोहे पर टैक्स बढ़ाने

[श्री सूरज प्रसाद]

का मतलब यह है कि किसानों के जो इम्प्लीमेंटस हैं, ट्रैक्टर हैं, किसानों के फावड़े और कुदाल हैं, उनके दाम बढ़ेंगे। इस तरह से सरकार का जो टैक्सेज बढ़ाने का तरीका है उस तरीके से आम जनता की तकलीफें बढ़ती हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि सरकार को अगर पैसे की जरूरत हो तो वह गरीब आदमी की पाकेट को कम छुवे। सरकार को चाहिए था कि हिन्दुस्तान के मिल्योनियर्स के ऊपर डाइरेक्ट टैक्सेज बढ़ाने चाहिए। हिन्दुस्तान के जो 75 मोनोपोली हाउसेज हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार ने टैक्स किसके बढ़ाए ? आम लोगों के।

आज आम लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है और इसी वजह से आम जनता की परेशानी बढ़ रही है। हिन्दुस्तान में पैसे की कमी नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि पैसा लेने के लिए सरकार के पास पोलिटिकल बिल है या नहीं ? आज सरकार में पोलिटिकल बिल की बहुत बड़ी कमी है। जिस जगह से पैसा लेना चाहिए वहां से सरकार नहीं लेती है और जहां से पैसा नहीं लेना चाहिए वहां से सरकार पैसा लेती है। वह उन लोगों की जेबों में हाथ डालती है जिनकी जेबों में पैसे की कमी है और वह उनके जेबों में हाथ नहीं मारती जिनकी जेबों में पैसा भरा पड़ा है। इसलिए आज हमारे देश के अन्दर जो परिस्थिति पैदा हो गई है उसका प्रधान कारण यही है। तुलसीदास जी की एक चौपाई है:—जहां सुमति वहां सम्पति नाना, जहां कुमति तहां विपति निदाना। जहां पर अच्छी मति, अक्ल होती है वहां पर पैसे की कमी नहीं होती है और जहां अच्छी मति नहीं होती है वहां पर हमेशा गरीबी और पैसे की कमी रहती है। इसलिए हमको लगता है कि सरकार की जो मति होनी चाहिए, जो अच्छी मति होनी चाहिए वह अभी नहीं है। वह समाजवाद की बात करती है, लेकिन उसमें टाटा भी रहेंगे, बिड़ला भी रहेंगे, तो क्या इस तरह से देश में समाजवाद आ सकता है।

जहां तक टैक्स बढ़ाने का सवाल है वह अमीरों पर ज्यादा पड़ना चाहिए और यही देश में समाजवाद लाने का बढ़िया तरीका है कि जो हमारे देश में 75 बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके जो कारखाने हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। अगर सरकार इस तरह की बात करती है तब ही उसके पास पैसा हो सकता है (*Interruption*)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को मिटाने के लिए जो दूसरा नारा होना चाहिए वह देहात के अन्दर जमीन का बंटवारे का है। हम देखते हैं कि सरकार ने इस संबंध में जो कदम उठाये हैं वे बहुत कम है। जमीन के बारे में कानून तो पास हो गये हैं और पहिले कहा गया था कि 1972 तक जमीन का बंटवारा कर दिया जायेगा, लेकिन अब यह कहा जाने लगा है कि यह कार्य अब 1973 में किया जायेगा। इस संबंध में कुछ राज्यों में तो कानून बन गये हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पार्टियां जमीन के बंटवारे को चाहती हैं क्या सरकार उनकी कोई कमेटी बनाने जा रही है ताकि वह इस कार्य को अच्छी तरह से देखे कि इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? हम तो समझते हैं कि उसका कोई भी दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि वह अभी तक इस संबंध में कोई भी बिल नहीं ला सकी है जिसमें इस तरह की चीज का प्रावधान किया जा सके। अगर सरकार देहात में जमीन का बंटवारा नहीं करेगी तो फिर अमीर और गरीब की खाई को किस तरह से दूर कर सकेगी ? इस बात की तरफ सरकार को सोचना चाहिए और कुछ न कुछ कार्य जल्द से जल्द करना चाहिए।

दूसरी बात मैं अन्न के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने अन्न के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया है, लेकिन अन्न के व्यापार के साथ दो प्रश्न जुड़े हुए हैं। पहिला प्रश्न और रोष किसानों का सरकार के ऊपर गेहूं के दाम के सम्बन्ध में है। दूसरा रोष किसानों का सरकार के प्रति यह है कि सरकार उनसे तो अन्न लेती है लेकिन उसके बदले में क्या देती है। किसान कहता है कि वह केवल बेचने वाला ही नहीं है बल्कि खरीदने वाला भी है। जहां तक उसके अन्न के प्राइस की बात है वह कहता है कि वह रेम्युनरेटिव नहीं है। जो उसको इस समय दाम दिये गये हैं वे चार पांच साल पहिले तय किये गये थे। इस बीच में किसानों का उत्पादन का खर्चा बढ़ गया है, दूसरी चीजों के खर्चे बढ़ गये हैं, खाद की कीमत

बढ़ गई है, पानी का टैक्स बढ़ गया है और इस तरह से दूसरे उसके चार पांच चीजों के खर्चे बढ़ गये हैं। अब कोई कारण नहीं दिखलाई देता है कि उसके अन्न के दाम के सम्बन्ध में फिर से विचार न किया जाय। अब प्रश्न यह है और मेरा ख्याल यह है कि किसानों को अवश्य रेम्युनरेटिव प्राइस मिलना चाहिए क्योंकि किसानों का कहना है कि जब सरकार हम से अनाज खरीदती है, तो उसे भी हमें कपड़ा, लोहा, तेल, बिजली खाद और दूसरी उसकी आवश्यकता की चीजों को एक दाम पर देना चाहिए। आज सरकार इन चीजों को देने के लिए तैयार नहीं है। वह उसका सामान लेने के लिए तो तैयार है और यही कारण है कि आज किसानों में सरकार के प्रति रोष है जो कि स्वाभाविक है। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि उसका यह आदेश होना चाहिए कि जितनी भी हिन्दुस्तान के अन्दर कपड़ा बनाने वाली मिलें हैं, वे हर तीन महीने के अन्दर 100 मिलियन कंट्रोल का कपड़ा तैयार करें।

अब उसको 120 मिलियन मीटर बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन यह कपड़ा क्या देहात तक पहुंचता है? नहीं? एक भी दुकान सरकार की ओर से देहात में नहीं खोली गई है जिससे किसानों को उचित कीमत पर ये चीजें मिल सकें। जहां तक खाद का प्रश्न है किसानों को खाद की जरूरत होती है और गत साल किसानों ने खाद ब्लेक में खरीदी और अमोनियम सल्फेट जो 56 रुपए बैग आती है उसको उन्होंने 80-90 रुपये बैग खरीदा। मुझे जानकारी हुई है कि खाद पर 25-30 परसेंट सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि जितने भी किसानों की जरूरत के खाद है अमोनियम सल्फेट और सुपर फास्फेट उन पर से एक्साइज ड्यूटी हटा दे या कम कर दे ताकि किसानों को सस्ती दर पर खाद मिल सके।

किसानों को ट्रैक्टर की जरूरत होती है और उस पर भी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। उसकी कीमत में गत 1-2 सालों में काफी इजाफा हो गया है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ट्रैक्टर्स पर से एक्साइज ड्यूटी हटाएगी? अगर सरकार यह करे, कपड़ा मुहैया करे, किरोसिन तेल दे तो हमारा ख्याल है कि किसानों को अनाज देने में हिचक नहीं होगी। मैं मानता हूं कि पंजाब और हरियाणा में सरकार की फिक्स्ड कीमत और मार्केट प्राइस में अन्तर नहीं है, लेकिन जहां तक यू०पी० का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, प्रश्न है, मुझे जानकारी है कि यहां मार्केट प्राइस में और गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड प्राइस में बहुत फर्क है और इसीलिए इन जगहों में सरकार को अन्न मिलने में काफी दिक्कत होगी।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि सरकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है। सरकार का जो इन्टर्नल कर्ज है वह 86 अरब है और विदेशी कर्ज 75 अरब है। हमारे यहां चार्वाक दार्शनिक हुए हैं। उनका कहना था 'यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृत्वा पीवेत'। मालूम होता है कि सरकार ने यह लक्ष्य बना लिया है कि जितना भी चाहो कर्ज लो और मौज उड़ाओ। सरकार को हर साल 700 करोड़ रुपया इसके लिए इन्टरेस्ट देना पड़ता है और फिर आम जनता के पास जाना पड़ता है कि हमको पैसा दे दो ताकि हम दूसरे कामों में खर्च करें। क्यों नहीं सरकार कर्ज लेने के बजाय दूसरे साधन को खोजती। हिन्दुस्तान के अन्दर 75 बिग हाउसेज है, उनके पास काफी पूंजी है, करीब 3800 करोड़ रुपए उनके पास पूंजी है जिससे उनको अरबों रुपया मुनाफा होता है। अगर उसका राष्ट्रीयकरण हो जाय तो उसको काफी अधिक पैसा मिल सकता है उसे देश के विकास में खर्च किया जा सकता है।

पी०एल० 480 का प्रश्न है। उसमें 1500 करोड़ रुपए का अभी तक फंड था। अभी क्या पोजीशन है, मुझको जानकारी नहीं है। सुनते हैं 400 करोड़ रुपया अभी भी पी०एल० 480 में है। यह फंड इस्तेमाल होता है सी०आई०ए० के विकास पर, सी०आई०ए० का फंड इस्तेमाल होता है कुछ पोलिटिकल पार्टीज को पैसा देने में, हिन्दुस्तान के अन्दर ईसाई धर्म के प्रसार में। मैं सरकार से जानना चाहता हूं—रस्क साहब अभी यहां थे—कि क्या आपने रस्क साहब इस बात को पूछा कि पी०एल० 480 का फंड हम राइट-आफ करने के पक्ष में है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पी० एल० 480 का फंड पौलिटिकल

[श्री सूरज प्रसाद]

पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होता है और इसलिए इस फंड को राइट आफ करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

यहां हिन्दुस्तान के अन्दर जुडीशियरी का प्रश्न उठाया गया। प्रश्न यह नहीं है कि कौन जज को सुपरसीड किया गया, कौन सुपरसीड नहीं किया गया। यह बुनियादी प्रश्न नहीं है। बुनियादी प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान की जुडीशियरी सुप्रीम है या हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट था उसने पार्लियामेंट द्वारा जनता के पक्ष में पास किए गए तमाम कानूनों के खिलाफ काम किया। उसने बैंक के राष्ट्रीयकरण को नलीफाइ करके 20-22 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों को दिलवा दिया। उसने राजाओं के प्रिवीपर्स को उठाने को रद्द कर दिया। अभी उसने जो संविधान में संशोधन हुआ था उसका 31(सी) धारा को नल एण्ड वाइड कर दिया। तो हिन्दुस्तान में सुप्रीम कोर्ट आज एक तीसरे लेजिस्लेचर के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए हम समझते हैं कि प्रश्न नये जजों की बहाली करने का है। जो जज सही माने में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को समझें उनको बहाल किया जाए यह सही कदम है।

बेकारों को काम देने का प्रश्न है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार में अभी बिहार के उद्योग मंत्री को कुछ लोगों ने तो पढ़े-लिखे इंजीनियर हैं उनको एक मीटिंग में बुलाया। उसमें चीफ मिनिस्टर नहीं आये, उद्योग मंत्री आये थे। उनका कहना था कि हम जब रुपये के लिए सरकार के पास जाते हैं तो हमसे घूस मांगी जाती है। जो चीजें हम पैदा करते हैं उनके लिए हमारे पास बाजार नहीं है। इसलिए उन्होंने सरकार से कहा कि आप अपनी मशीनरी को डाइरेक्शन दीजिए कि हमको बिना घूस के रुपया मिले और जो चीजें हम पैदा करें उनके लिए बाजार होना चाहिए। यह स्थिति बिहार की ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान की है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि रुपया देने की जो मशीनरी है, उसमें जो करप्शन है और भ्रष्टाचार है, उसमें सरकार इतनी रोक लगाये ताकि जो इंजीनियर, जो सैल्फइम्प्लायमेंट चाहते हैं उनको काम मिल सके और जो चीजें वह पैदा करते हैं उनकी बिक्री का भी वह इंतजाम करे।

SHRI DAHYABHAI V, PATEL (Quia-rat): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Appropriation Bill contains Demands for Grants for many Ministries and I would like to begin with the Departments that are particularly under the care of the honourable Ministersr sitting opposite. Sir, he is in-charge of Revenue, that is, taxes, Income-Tax and so on. With all humility, Sir, I would suggest to him that before recruiting anyone for the Income-Tax Office, he should put them in a class on good manners and teach them how to behave with the citizens. I can show him dozens of letters that I have received, that my friends have received, which are very rude, which no servant of the people should ever write. After all, Sir, every Government servant is a servant of the people and as long as a man is not found to be dishonest or a tax-evader he is lo be treated as an honest citizen. I have letters, rude letters, written to me, asking for the payment of Income-Tax for this year and that year, for four or Ave years, though the amount has actually been paid and for writing this notice and

I serving it on me, a charge of one rupee has been made! Sir, this is a ridiculous state of affairs. The Income-Tax Officer who fails to do his duty of looking into the flies and rinding out whether the money has been received or has not been received, simply issues a blanket notice for the years 1966-67, 1967-68, 1968-69 and so on indicating that a large amount has been paid. This harassment of amount has been paid. This harassment of the public must stop. It must be a two-way traffic if you have to be fair.

Sir, in this House, we know the treatment meted cut to the people there, the higher-ups, the people on the other side and how they have been dealt with even in the matter of forgetting to pay the In-c6me-Tax and I do not want to go into those matters i.nd I do not want to repeat tHc names of the people and I have no animus against them. What I am asking for is fair treatment to all. In this country, since we have a democracy, every citizen *must* be equal and as long as a citizen pays his taxes honestly he should be treated as an honest citizen.

SHRI MAHAVIR TYAGI: This year I also feel like forgetting^

SHRI DAHVABHAI V. PATEL: We all feel like forgetting because the prices have gone up and *garibi hat gayi* for them and not for us. *Curibi* is *haloed* for the opposite side; it has brought ten lakhs from the exchequer indirectly or directly. For us it is *garibi, garibi* and *garibi* all the time. Sir, apart from this diversion 1 would request the hon. Minister once again to look into this, If he is anxious, I can give the letters also to him. Is it not the duty of the Income-tax Officer to make sure whether the payment has been received before sending this notice. And he serves the notice at our cost; he charges one rupee for this notice which is absolutely untrue? I think he should take note of it and take action against such person and charge him one rupee and refund that one rupee to the assessee...

SHRI MAHAVIR TYAGI; I think the Minister will be thankful if you pass on the letters.

vSHRI DAHVABHAI V. PATEL: I do not think so...

SHRI K. R. GANESH: Sir, there ore two things. First, you have made a general complaint. If you give any specific thing, I shall look into this. The Income-tax Officer issues notices in the prescribed form. Unfortunately, if it is a prescribed form I cannot help it. But if you can give me anything which is not so, I will definitely look into it.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL; My suggestion is that the prescribed form be altered. It should be incumbent upon the officer, before he issues that notice, to make sure whether the payment has been made or not. Is it not a justifiable demand that I am making? That is what I am asking for...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. 3. RAJU): Have you got any specific case?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Not one; I can cite several cases. The other | point concerns me. I am here in Parliament doing my duty, because I am summoned by the President. Income-tax notices are sent to my house, pushed into the door whether anybody is there or not or even if a neighbour signs who does not know anything, in spite of the fact that I have written several times to the Income-tax Officer pointing out that so and so is my Income-tax consultant. Not that I am a rich man or can afford having income-tax consultants. I am a small man. But be was my co-student in Gujarat Vidyapeeth and he became an accountant and consultant in income-tax. He works for pie as an old friend and associate. He does this work while I am here and he has also written to them to send these notices to his office which is in Bombay, which is only 5 minutes' walk from my house, instead of sending it to me. He has pointed out to them that it will serve the Department better also instead of causing all this confusion. This is the specific instance I am giving, lint the Income-tax Officer absolutely disregards this, even though he has been told about this more than once.

Sir, it is possible that certain new people have been made Income-tax Officers and they are not aware of this. This brings me to another matter which is also important,

People are sent on deputation from one department to another. In Government service, as the Rules are, if a man is a failure in one place, he is sent to another place. And under the benign Congress Government if you are in the good books of the Ministry, you are sent to another department even though you arc a total failure; instead of being condemned you are sent to anpthei department and you get 25 per , cent deputation allowance—for harassing people of the Opposition. Is it a right thing to do? I would like to know. . . . This is not the right way of doing things. You say that you want to economise. Is it economy? You-transfer people on deputation and give them 25 per cent. . ,

SHRI K. R. GANESH: This is not correct. I am sorry if any harassment has been caused to him. No harassment should

[Shri K/R Gancsh.J be-dona .to any assessee. But. Sir., probably in his anger he is presuming too many things. There is no question of a deputa-tionist being an Income-tax Officer. It is *j.* highly centralized service. And without even going into the records, I can straightaway answer that there is no question of a deputationist from other Departments to become Income-tax Officer. I want to clear the fear which the hon. Member has got.

SHRI MAHAVIR TYAGI: I concluded that he was just pointing out to a way for effecting economy. There are thousands of people on deputation. It is not so in the Income-Tax Department alone. A man goes from one office to another and he gets an allowance. Like thai, thousands of people are getting deputation allowance. If you stop this, you can have a saving of one crore of rupees.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I am thankful to my colleague for clarifying the position. I do not say thai this gentleman who sends the notice is a man on deputation. The important point is that there are hundreds of people who are still on deputation. If they are found unfit in one place,, they are sent to another place on deputation and they get 25 per cent.

THE VICb-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Do you presume that if one officer goes from one Department to another Department, he gets deputation allowance?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I would like to know how many are on deputation.

SHRI MAHAVIR TYAGI: If one employee is sent to another Department, he gets deputation allowance. Similar is the case when there is a Commission or a Committee. He is sent on deputation and deputation allowance is given.

SHRI K. R. GANESH: I will explain the position in my reply. I do not think that it is as large as the hon. Member has tried to make. out. . Many a time, questions have been asked on this. 1 will try to give as many facts as are necessary about how jrtawy people are on deputation and what the expenditure on them is. I do not think, subject to correction, that the dimension of the problem is so large as to become the subject-matter of the hon. Member's submission in an Appropriation Bill. This is a very marginal problem as far as the administration is concerned.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): He has promised to find it out.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: The next point I would like to make is that the Government of India is forgetting its promises. Prime Minister, Indira Gandhi, made a promisfe in this House and in the other House about the taxes imposed when the war with Pakistan and the Bangladesh issues were before us. Every letter had to be stamped by 5. P. more and when it was withdrawn, it was said in the House that the money on these stamps would be refunded. Shall I show you how many stamps the post office has refused? They refused to take hack the 20 P. envelopes with a stamp for 5P. stuck on them because the stamp had been stuck on the envelopes. The envelopes were not defaced or used. The post office refused to take them. I say it is dishonesty. There must be some sense of honesty and shame in this Government. They turn round completely on the promises they have given publicly in this House. Similar should be the case with your air letters, foreign or Indian, on which the stamp has been stuck. It has been given in that form by. your post office. I did not stick them or I did no manufacture them. The hon. Minister must keep his word to the people in this matter.

Sir, another point on which I wish to draw the attention of this House is the Maharaja Air Terminal that has been built at Bombay. A huge building, a sky-scrapper has been put up for the terminal of Air India as also the Indian Airlines. Though the building is under the same Maharaja, the Indian Airlines pays one lakh of rupees as rent to Air India. The Indian Airlines could have put up its own

building. That is an indirect way of transferring the money from one pocket to another. The rent is one lakh of rupees a year. A tremendous amount of inconvenience was suffered by the people of Bombay during this one year because when the building was ready, the approach roads were not ready. There were *kacha* roads for several months with metal on them not rolled.

It was difficult to take a car. And what about the baggage? How do you take the baggage if the car does not go to the terminal? And then, when you go one way the police man says: You cannot go this way. If you go the other way, the Air India man comes and says: You cannot go this way. In whose benefit is this Maharaja working. There is an utter lack of coordination between the two Ministries unless it is admitted that it is wanting to take money from one pocket and put it into the other. Is it not the reason why the Indian Airlines has been paying this expenditure again and again which is unnecessary and unjustifiable? The Indian Airlines had a terminal before they came to the new building. Was it not good enough? Nobody complained of inconvenience. It was not right in the heart of the city. Nobody wanted it. It was at one end but there was a good road, there was a tram and there was a bus. At this place there is hardly any traffic at night. 1 do not know what happens to the staff, to the air hostesses and the lady staff. How do they go home after 10 p.m.? What happens to the passengers who come in air coaches and are dropped there? At whose mercy are they dropped there? This is absolutely an unjustifiable expenditure. If the Indian Airlines had to put up its own building there is a plenty of land there. The Government of Bombay would have been glad to give it on one lakh of rupees. The Indian Airlines could have built its own buliding instead of taking it on an annual rent of Rs. 1 lakh.

Why do you want to waste money? Is it that the Air India should look better on its plans, at the expense of the travelling public of the Indian Airlines? I think

this is not the right way of accounting and this must be set right.

Sir, in this House yesterday and today we have heard so much of law and order situation. It is indeed a sad commentary on our democracy that in the capital city of Delhi this law and order situation should prevail. I do not know if the strongest words would be enough to condemn an administration where this sort of thing prevails and where the Government had due warning of this. Of course, it suits some of my friends, my friend who sits next to me. Their interest lies in creating chaos and confusion so that there could be an excuse for them to get more and more power.

SHRI MAHAVIR TYAGI: It is their calculated policy...

SHRI DAHYABHAI V. PATFL: They want to get more and more power into their hands, to get regimented and then to say that the democracy in this country has failed. Are the subjects taken one by one pointing to that direction?

Sir in this House, during the last session, I voiced perhaps the lone voice against the takeover of foodgrains and I had pointed out what the consequences would be. Every word of it has come to be true. I said: You have not got the machinery, you have not got the experience, you have not got the buffer stocks, what you are referring to as buffer stocks are only 'bluffer' stocks. And Mr. Shinde went on giving right or wrong figures. He makes one statement here and another statement in Satara. How can a responsible Minister behave like this? I think the Food Ministry has behaved in the most irresponsible manner with the country.

Sir, do you know in Gujarat even now what the ration is? One kilo a month is the ration that is given. Tyagiji, would you be able to live on one kilo a month? The poor agriculturist and the poor labourer is expected to exist on one kilo of ration per month.

SHRI MAHAVIR TYAGI : It is official?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: That is what is officially available. They say (his is what is available. Under the new Congress dispensation they give what is available. They have got one kilo only and they give one kilo". 1 have said about the present state of affairs in the Congress Government in the State of Gujarat. There is so much of infighting that they cannot agree on anything. And the Chief Minister of course sits here. The Prime Minister here is the Chief Minister of Gujarat virtually because for every little thing they have to come here and take her orders. That is how that Government is run. That is how they have decided on one kilo of ration per month. I had mentioned, don't do this in a hurry; you will rue the day when you took this step of taking over of food grains trade because you have not got the experience, you have not got the machinery and you have not got the stocks. How can you do it? It is a very hasty step. Don't rush into this where saner people would think twice before doinc it. I hope the hon. Minister remembers what I said: 1 do not know whether he was there or not.

SHRI K. R. GANESH: We have BOM in for that and there is no going back on it now. Now it is only a question of facing whatever will be there.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : I do not know how you are going to do this except by bullets ; and that you have already done. There have been five firings in Gujarat already; do you know that? Five times there have been firings in Gujarat just because people asked for rations. I do not know whether the hon. Ministers remember the story of the Queen who said, if they have no bread, why don't they eat cakes?

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu): It was Marie Antonette who said that.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I ami sure he knows it. Is it not what this-Government is doing? 1 want to ask you; how do you expect the people to have confidence in a Government that behaves like this?

AN HON. MEMBER: Massive mandate.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Thai is the result of the massive mandate. Are the people being punished for the massive mandate that they gave?

Sir, we have been told that arrangements are being made in some places to give 1.5 kilos, in some places 2.5 kilos...

SHRI MAHAVIR TV'AGI: Per month?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Yes. per month. And in some places they will give 7 kilos. Did not the Prime Minister say so a few days back at Kanpur? Is this going to satisfy the people? And does she expect people to keep quiet on this? Does she expect people to go home and sleep hungry day after day? Then what is the remedy? Instead of *garibi halao* we know what we have got. The price of everything has gone up and the major reason for this increase in price, of course, is the greed of the Government. Is there any item of ordinary consumption on which there is not 25, 30 or 40 per cent excise duty imposed by Government? You take the ordinary box of matches. If you go and buy one rupee worth of matches in the market today 75 to 80 paise out of that rupee account for the taxes of Government directly or indirectly. There is tax on wood, tax on sulphur, tax on paper, tax on printing, tax on sales. You add it up and you will know how much it comes to. I have calculated it. Ask your Department to calculate it for you. I have not only calculated ; I have printed and published a paper four or five years ago. And the situation has not improved after that. How are you going to remove *xuribi* at this rate and where are you taking this country?

Last but not the least, we call ourselves a democracy. In a democracy where there is no food, in a democracy where there is no law and order, where do people look to? The only hope for the people, when this type of dictatorial Government takes charge, is the court and now the independence of the judiciary is being undermined. You want a set of I committed judges. Those wbo are not: committee will be sent out summarily. Is this democracy? Why do you not give up this dishonest boasting of being a democracy? Say that we are a totalitarian Government. We will copy what they do in the Soviet Union. That is the easiest way. When there is too much population, shoot them down as they did in Russia. Even with that, let me warn you, tfcey did not have enough food and today after fifty years or sixty years of socialism or communism, whatever vou call it, they have to import food from America and Canada and you call the Soviets your best friend. They are a wise people. 1 do not know what we are. We do not seem to learn lessons even from them. They foresaw what the situation in India is going to be, because we have got so many Russian experts all over the country and they know every inch of what is happening. They foresaw that there was going to be a shortage of food and they went and bought up all the wheat available in America and Canada before us. They were able to buy at a thirty per cent lower price. When we went to buy there was hardly anything available and what was available they sold at a rate thirty per cent higher. I do not know whether they were selling to us at a profit of thirty per cent or not, but this country, this Government had to buy it at thirty per cent higher than what the Soviet got. That shows how we are managing our affairs and our good friends, the Russians, are managing us. How can we blame the Russians, if we are going to be so foolish? It we are foolish, anybody will do it. Why do we not alter this policy? Why do we not take lessons from the past? Have not Russians/the Soviets, done this to other countries before? They have done it and there is more than one example. We protested against what they did to Czechoslovakia and why are we acquiescing today in this? You are taking the country to ruination by all these policies. Whether politically motivated *or* economically motivated, the policies of this Government are not in the interests of the country. The policies need to be changed, economically and politically, so that they are primarily for the benefit of the people of this country. I am afraid that is not so, and, therefore, we are going wrong. Thank you.

tSHRl M. KAMALANATHAN (Tamil Nadu): Hon. Mr. Vice-Chairman, Sir, 1 rise to express my views on the Appropriation Bill for the year 1973.

Sir, I am deeply pained to point out that All India Radio has become an instrument of political propaganda for the Indira Congress. It will not be an exaggeration to say that the All India Radio is being utilised as a propaganda weapon for the ruling party here. 1 happened to come across a cartoon in *The Hindustan Times* which depicted that the Minister of Information and Broadcasting sneezed three times and that was televised.- I am sorry to say that the All India Radio and the Television are being used for the ends ol the ruling party here.

You must be knowing, Sir, that recently in Tamil Nadu a cinema actor has started a new political party. From the manner in which the All India Radio is giving importance to the emergence ol this political party, it is apparent that the Indira Congress has not only instigated the formation of this party, but also is giving protection and patronage for the survival of this party. I have no hesitation in saying that this new party is being propped up by the Indira Congress. If you switch over at any time to the News in Tamil, there will not be anv occasion in which there is no reference to MGR's party. The public propaganda media give so much importance to a new regional party. The other political parties are not treated on the same footing

' tOriginal speech in Tamil.

[Shri M. Kamalanathan.] by the All India Radio. I charge this Government with the dereliction of sacred trust reposed in them by showing this kind of virulent partiality and preferences.

In 1972 the massive mandate of the people was sought by the ruling Indira Congress on the *magna curia* of instant socialism. But, what do we find? We find that the tendencies of dictatorship are getting the upper hand in our country. Socialism is as elusive as it was before.

Recently, our Prime Minister visited Sri Lanka and she is reported to have had wide range of discussions with the Prime Minister of Sri Lanka regarding repatriation of people of Indian origin and about Kachchathivu. I would like to express my views about Kachchathivu. Sir, Kachchathivu is part of Tamil Nadu and Tiimil Nadu is part of Indian Union. Therefore, Kachchathivu is part of Indian Union. The Tamil Nadu Government have got authoritative documents to prove that Kachchathivu belongs to Indian Union. This was a part of Ramanathapuram *Zumin* and the Ramanathapuram Maharaja used to collect land revenue in Kachchathivu. Two years ago, in the Tamil Nadu Assembly, the then leader of Swatantra Party placed on the Table of the House authoritative documents conclusively proving that Kachchathivu belonged to Tamil Nadu. You will no doubt be surprised to know the name of this Swatantra Party leader. His name is Seomaichamy, who is now contesting the Parliamentary election in Dindigul on the ticket of Indira Congress. We are afraid that our Prime Minister has entered into some secret pact with the Prime Minister of Sri Lanka for handing over Kachchathivu to Sri Lanka. She is reported to have stated that it is not a place of any strategic importance, but only a rocky place.

SHRI MAHAVIR TYAGI : No Prime Minister can transfer our territory.

SHRI M. KAMALANATHAN : I would come to my hon. colleague Shri Mahavir Tyagi also. When the Chinese staked their claim for Aksai Chin, the father of our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, asserted that not even an inch of land where a blade of grass does not grow will be ever given to a foreign country. Shri Mahavir Tyagi in a jocular vein stated whether his head can be demanded by somebody because not even a single hair is there.

In West Bengal, without consulting the State Government of West Bengal, Bern Bari was gifted away to Pakistan. Here, in the case of Kachchathivu, the Tamil Nadu Government have got documentations to prove that it belongs to Indian Union. The people of our country should be assured by our Prime Minister that she would first have consultations with the Government of Tamil Nadu regarding Kachchathivu and then she would negotiate with Shri Lanka from a position of strength. You know about Kanya Kumari, the southern-most tip of our country. We have now Vivekananda statue on the rock on which he was stated to have had the vision of future India. If Kachchathivu is handed over to Sri Lanka, then you will find a Chinese sitting under this statue. You will have Chinese in the North and Chinese in the South. Then, naturally the defence of our country will be in jeopardy. I appeal to the hon. Prime Minister that before she takes any definite decision she must have prior consultations with the State Government of Tamil Nadu and she must not hand over Kachchathivu to Sri Lanka.

Sir, under Sirimavo Bandaranaike-Lal Bahadur Shastri Pact, 10 lakhs of people of Indian origin living in Sri Lanka are to be repatriated. A majority of them hail from Tamil Nadu and Kerala. In this Pact there is reference to 5.25 lakhs of people who would be repatriated and also to about 3 lakhs of people who would be given the citizenship rights in Sri Lanka. Unfortunately there is no reference to 1.75 lakhs of Stateless people of Indian origin living in Sri Lanka. Even in the case of refugees who have come to India, I am sorry to say that adequate attention

has not been paid by the Central Government for their rehabilitation. Shri K. R. Ganesh, who comes from Andamans, knows that there are any number of rubber plantations in Andamans. There was a proposal to repatriate one thousand families of refugees from Sri Lanka in Andamans. So far, only one family has been repatriated in Andamans. Before this problem assumes menacing proportions, 1 request the hon. Prime Minister that immediate efforts must be taken in the matter of rehabilitating repatriates from Sri Lanka.

Sir, I regret to point out that the Income-tax Department is being used as a political weapon and for political blackmailing. I am happy that Shri Ganesh has become attentive to hear what I am going to say. In the whole country, the cinema actor of Tamil Nadu. Shri M. G. Ramachandran, who is being protected and propped up by the ruling parly here, is the person against whom the largest amount of income-tax arrears stand. The Income-tax authorities went to his house with the attachment warrant. But. Shri M. G. Ramachandran rushed to the High Court at obtained a stay order. As soon as this was done, the Income-tax authorities vanished in the thin air. We do not know what compromise has been arrived at between Shri M. G. Ramachandran and the Income-tax officials. Later on, Shri M. G. Ramachandran withdrew the case from the Court. It is also a fact that so far the Income-tax Department has not taken any action for recovering the arrears from Shri M. G. Ramachandran. I would request the hon. Minister of State in the Ministry of Finance, Shri K. R. Ganesh to explain the action taken by the Department to recover the income-tax arrears from Shri M. G. Ramachandran.

Sir, Shri K. R. Ganesh hails from Andamans. Though he is not visiting Andamans frequently, he visits Tamil Nadu again and again at regular intervals. We do not know his connections in Tamil Nadu. As compared to other Central Ministers, Shri Ganesh does not visit Andhra Pradesh, Maharashtra or for that matter any other State as frequently as he visits Tamil Nadu. It would be proper if the Income-tax Officers are there to welcome him during such visits. He may have his friends also to receive him. But, there is one lady, Dr. Vijayalakshmi, who is always in the forefront of his admirers in Tamil Nadu. Whether Shri Ganesh goes to the Income-tax Officer or to the Customs Office, he is always accompanied by Dr. Vijayalakshmi. This has led the local people to doubt whether Shri Ganesh is the Minister or Dr. Vijayalakshmi is the Minister. She has become so popular and influential in Tamil Nadu. Whatever might be the income-tax arrears, the people of Tamil Nadu are not afraid, because they have confidence that Dr. Vijayalakshmi will manage everything, and they are safe in her hands. I want to know whether it is proper to give so much importance to a private individual even if that individual belongs to the ruling party. The Income-tax Officers are in shivers at her sight and it is rumoured that there is interference from her side in their working. I have brought this to your notice and through you to the notice of the Prime Minister so that some steps can be contemplated to remove such misapprehensions from the minds of the people there.

With these words, I conclude.

SHRI K. R. GANESH : I deny the allegation that the hon'ble Member is making. I am surprised that the hon'ble Member should stoop to this level as a result of his confusion in relation to certain matters which have arisen in Tamil Nadu in relation to his party. He is bringing in issues which have no relevance to the subject. I deny all the allegations that have been made. I deny that there is any interference in the work of our department. Sir, if there is at all any interference, we are trying to assess the interference. The interference is from very high quarters. I am afraid this is one thing the hon'ble Member should not have brought. It is not possible for the Income-tax Officers or the Commissioner of Income-tax to function in a manner in which he should function with liberty. The whole of the

[Shri K. R. Ganesh.]

Income Tax Department is being watched by the Government to which the hon'ble Member belongs. As I said, it is hardly a matter he should have brought 5 P.M. on the floor of the House. He should know that I am in possession of facts which he cannot have.

He mentioned about MGR. As far as MGR is concerned, he is as any other assessee. There are large arrears. We have given those facts as far as Parliament is concerned. He had gone to the High Court against certain assessments made. Certain assessments are disputed. Then he has withdrawn his petition from the High Court and gone to the Income-tax Department for settlement. Now, as you know, settlement is within the framework of the law. The Commissioner of Income-tax is going into the merits or demerits of the settlement petition that he has made. This is the exact position as far as the question of MGR is concerned. The hon. Member, instead of trying to meet this problem in a political manner, is trying to put all that on the Income-tax Department. It is not a correct thing. I challenge the hon. Member.

SHRI M. KAMALANATHAN : I also challenge you.

SHRI K. R. GANESH : I challenge you. You know that I had all my political life in Tamil Nadu. I know as much of Tamil Nadu as you know. You cannot prevent an Indian citizen from going to any part of India. For ten years I have been there. I know all parts of the districts. I know everything that has happened in Tamil Nadu. You cannot shut me out from entering Tamil Nadu or from taking part in the political activities of the party to which I belong. He cannot prevent me. He knows that the Income-tax Department is not politically motivated. The job of the Income-tax Department is to catch tax-evaders, to catch people who are evading taxes, and to see that we get the revenue that we have there. I am surprised that the hon. Member in his frustration should have brought out this charge.

SHRI M, KAMALANATHAN : There is no frustration.

SHRI K. R. GANESH : I am not as free as he is. Being a Minister of the Central Government, I speak with great solemnity. Being a Minister of the Central Government, I have some responsibility. I cannot accuse as he is trying to accuse because if I had that liberty, the hon. Member will not be sitting here. Sir, on the floor of this House, I solemnly ask the hon. Member, through you, Sir, let there be an enquiry into the activities of the Income-tax Department as far as Madras is concerned.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Mr. Barbora.

SHRI S. S. MARISWAMY : Sir, one clarification. The hon. Member had not accused him for making repeated trips to Madras. On the other hand, he is welcome to come to Madras. But the way he moves about in Madras gives room tor people to talk about it. So, with all good intentions he has asked him to be aware of the rumours that are set afloat in Madias. Secondly, he has said that the hon. Member has spoken in frustration. What is the frustration that the hon. Member can have ? The hon. Member has asked a question and the Minister is expected to give an answer. Why should he insinuate and attribute motives? This is unfair on the part of the hon. Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : The Member seems to have said—of course, he spoke in Tamil—that Mr. Ganesh belongs to Andamans and why he goes often to Madias.

SHRI S. S. MARISWAMY : That point is there. Then he said, you are repatriating lakhs and lakhs of Ceylon Tamilians to Madras; there was a move to settle them in Andamans; but up to now it has not been done. Since he comes from that area, he should take more interest; that is what he said. Andamans is a part of India; Madras is also a part of India. We welcome him. Rather let him come and settle down, after retirement, in Madras.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Let it end there.

SHRI K. R. GANESH : Sir, the hon. Member was not perhaps listening. When he was referring to my visits to Madras or Tamil Nadu, he said why I should go to Tamil Nadu. That is one point. Secondly, Sir, where my Commissioners cannot function, where their phones are bugged, where they cannot meet, where they have *to* meet out of their offices, I have to function with them.

SHRI S. S. MARISWAMY : Sir. it Is a serious allegation. I challenge the hon. Minister.

SHRI MAHAVIR TVAGI : How can the telephones be bugged by the State Government ?

SHRI K. R. GANESH : I said it with all the authority of a Minister. I say the telephones have been bugged.

SHRI MAHAVIR TYAGI : But telephones are not within the powers of the State Government. Telephones are under the Central Government.

SHRI S. S. MARISWAMY : Mr. Vice-Chairman. it is a very serious matter. Telephones are in the hands of the Central Government. The State Government cannot bug the telephone of the Income-Tax Commissioner or anybody for that matter. And the honourable Minister says that when he wants to talk to the Commissioner of Income-Tax, Madras, he has to go to Madias personally. He has made a substantial statement, a serious charge, against the State Government. He is a responsible Minister. In the same manner I can also tell him that his department is being used for blackmailing certain individuals. I say this with full facts. Though he may not be directly concerned, his people, the people with whom he is closely associated in Madras, are touts and brokers who go round and collect funds for his party. This is my statement and let him deny it.

SHRI K- R- GANESH : I deny all that he has said. I have already said that I deny all that he has said and I maintain that it is in the most adverse circumstances that the Income-Tax Department is working in Madras.

SHRI MAHAVIR TYAGI : If a department of the Central Government, the Income-Tax Department particularly, is not allowed freedom in any State, the Central Government must take action. They cannot allow this state of affairs to continue. If there is some such thing, I want to know whether the Central Government protested against this behaviour of the State Government or whether it has taken it lightly and borne it. If there is interference in the functioning of the Income-Tax Department from any State Government, it is for the Central Government to protest against and to safeguard. I want to know what action the Government has taken in this regard when it is within its knowledge. I want to know whether any action has been taken.

SHRI S. S. MARISWAMY : Mr. Vice-Chairman, it is a very serious matter. The Minister of State for Finance has levelled a serious charge against the State Government which is supposed to be functioning under the Constitution. He said the Madras Government bugs the telephones of the Income-Tax Department officers and that is why he cannot speak to his officers from Delhi on telephone and for that purpose he goes to Madras personally. This is a serious matter. I want the Government to come out with a statement on this.

SHRI MAHAVIR TYAGI : The question is not only about bugging telephones, why is not the State Government allowing the Income-tax Department to function ? Action must be taken against the State Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAIU) : The Minister has made a statement and it should be taken as what it means. There is no ambiguity about it. He said with all his authority. What is the use of discussing it?

SHRI MAHAVIR TYAGI : But action must be taken.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAIU) : Anyway, now Mr. Golap Barbora.

श्री गोलाप बरबोरा (**आसाम**) : उपसभाध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार केवल नारों की सरकार है और कोई ठोस काम की सरकार नहीं है, वह समाजवाद की तो सरकार है ही नहीं। देश में फिजूल बहुत सी चीजों पर बहस चलाई जा रही है और उसी में से एक था कांग्रेस सोशिलिस्ट फोरम और नेहरू फोरम । उस की बहस देश में काफी दिनों तक चली । उस के बाद प्रधान मंत्री जी का निर्देश हुआ कि दोनों फोरम्स की बात अब बंद करो । लोगों ने उनकी बात मान ली और कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम और नेहरू फोरम, दोनों का दरवाजा बंद हो गया । अब फिर से एक बहस खड़ी हो गयी है जुडिशियरी के बारे में । फ्रीडम आफ जुडिशियरी और कमिटेड जुडिशियरी, इन दोनों के बीच में सही रास्ता क्या है इस के लिए लोगों को सोचना चाहिए । जुडिशियरी की फ्रीडम की जहां तक बात है, मैं तो समझता हूं कि अभी भी कोई फ्रीडम उन को नहीं है क्योंकि जहां तक राष्ट्रपति की फ्रीडम का सवाल है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह देश में मेजारिटी पार्टी के वोटों से होता है और राष्ट्रपति को कोई खास फ्रीडम नहीं है और राष्ट्रपति नामिनेट करता है जुडिशियरी के लोगों को, खास कर चीफ जस्टिस को और जजेज को । तो जजेज को भी उस हद तक फ्रीडम नहीं है जिस हद तक कि उन को फ्रीडम होनी चाहिए ।

और अभी हाल में जो कुछ भी हुआ मिस्टर अजित राय को चीफ जस्टिस बनाने के बारे में तो कांग्रेसियों के साथ भी मेरी बातचीत हुई, कुछ लोग कमिटेड जुडिशियरी की बात करते हैं, कुछ प्रोग्रेसिव और रिएक्शनरी की बात करते हैं, ताज्जुब लगता है मुझे कि तीन चार जजेज जो थे उनमें कैसे श्री ए० के० राय प्रोग्रेसिव बन गये और और लोग कैसे रिएक्शनरी बन गये, इसके बारे में तहलका मचा । हेगड़े साहब का आज अखबार में बयान है, उन्होंने साफ इल्जाम लगाया कि प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर नाराज रहीं उसी वजह से यह सुपरसेशन का सवाल आया और प्राइम मिनिस्टर नाराज क्यों हुई उनके ऊपर । क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई जजमेंट उन्होंने किया था । प्राइम मिनिस्टर कानपुर में कहीं आम सभा में बोलीं हैं, प्राइम मिनिस्टर का वह बयान भी आज के प्रेस में है कि कानून को सस्ता बनाना चाहिये जिससे कि आम लोग कानून का फायदा उठा सकें, उसकी व्यवस्था होनी चाहिये । बहुत बढ़िया चीज है लेकिन इसके लिये क्या व्यवस्था आपने की है ? चीफ जस्टिस किसी को सुपरसीड कर के बना लेने से क्या आम लोगों तक कानून पहुंच जायगा ? ऐसी कोई बात नहीं है । आम लोगों को कानून की सुविधा देने के लिये कोई व्यवस्था देश में है नहीं । तो यह एक फिजूल की बहस अभी खड़ी कर दी गई है और इसी को एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव कदम, बहुत बड़ा समाजवादी कदम कांग्रेसी मानते हैं और इस फिजूल बहस-बाजी में लोगों का जो खास सवाल है, जो रोजी रोटी का सवाल है, जो मंहगाई का सवाल है, इस सब से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश है । अगर आप चाहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम हो या जुडिशियरी सुप्रीम हो तो कैसे हो ? अगर पार्लियामेंट को ही सुप्रीम मान लिया जाय तो साथ में यह भी मान लेना पड़ेगा कि मेजारिटी पार्टी सुप्रीम और मेजारिटी पार्टी सुप्रीम का मतलब कि मेजारिटी पार्टी का लीडर सुप्रीम तो फिर जा कर के कभी डिक्टेटरशिप सुप्रीम बन जाती है । पार्लियामेंट तो देश में सुप्रीम है, बल्कि नाहुदर जुडिशियरी नार पार्लियामेंट सुप्रीम तो पीपुल हैं, पीपुल की जो राय है, वह होनी चाहिय और जो कुछ व्यवस्था और कानून हो वह पीपुल के लिये होना चाहिये । वह तो देश में हो नहीं रहा है और फिजूल एक बहसबाजी देश में खड़ी कर दी गई है ।

नेशनल इंटेग्रेशन का सवाल है, नेशनल इंटेग्रेशन की बातें हम करते हैं, नेशनल इंटेग्रेशन कौंसिल को भी रिआर्गेनाइज करने की बात प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने कही है लेकिन अभी अभी

बिहार में बांका में पार्लियामेंट का उप-चुनाव हुआ था, हमारे हाउस के नेता हैं, माननीय होम मिनिस्टर साहब दीक्षित साहब वहां गये थे भाषण देने के लिये । दीक्षित साहब ने वहां मधु लिमये के खिलाफ बात कही । वह वहां कांग्रेस की नीति को नहीं बताया, दीक्षित साहब ने वहां पब्लिक मीटिंग में कहा कि मधु लिमिये बम्बई के रहने वाले हैं उनको बिहार में कंटेस्ट नहीं करना चाहिये लेकिन दीक्षित साहब को जवाब बांका की आम जनता ने दिया और कांग्रेसी की जमानत जब्त हुई और मधु लिमये 35 हजार वोटों से जीत कर आये हैं । तो ये लोग ऐसी ही बातें किया करते हैं । कहीं इंटेग्रेशन की बात करेंगे और कहीं जा कर के लोगों को प्रान्तीयता के सवाल पर लड़ायेंगे । मुसलमानों का वोट जब तक मिल जाता है ठीक है लेकिन जब कभी मुसलमानों में विरोध होता है तो उसके ऊपर डंडा चलता है । यह तरीका कांग्रेसियों का है । इससे इंटेग्रेशन कहीं होता नहीं है । देश में टूट-फूट की भावना आज दिन व दिन ज्यादा बढ़ती जाती है और सारे हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय विचार किसी का है नहीं, न तो कोई राष्ट्रीय नेता है । सरकारी दल में सब कोई अपने जिले या प्रान्त के नेता हैं, बात करते हैं राष्ट्रीयता की और कुछ करते ऐसा है नहीं । तो राष्ट्रीयता का विचार कोई उन लोगों के दिलों में नहीं रहता । मैं भी बचपन से एक समाजवादी हूं, कोई अमीर घर का आदमी नहीं हूं बहुत गरीब घर से आया हूं । समाजवाद का मतलब सिर्फ नेशनलाइजेशन नहीं है और नेशनलाइजेशन भी जिस ढंग का आज किया जा रहा है यह ग़लत है। एक एक इन्डस्ट्री को महीने दो महीने या तीन महीने बाद पकड़ कर आप राष्ट्रीयकरण कीजिए, उसको कांसालिडेट न कीजिए, फिर किसी और के राष्ट्रीयकरण के लिए दौड़ें इससे काम नहीं होता है । अगर आपको, कांग्रेस पार्टी को, मासिव्ह मैन्डेट है सोशलिज्म के लिए तो मासिव्ह मैन्डेट के बाद आपने उनको "टाई" कर देना चाहिए ताकि अगले 5 साल के अंदर हम उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें । अगर राष्ट्रीयकरण करना है तो फौरन राष्ट्रपति का आर्डिनेंस निकाल कर आगे बढ़ना चाहिए और वह सब टेक-ओवर करने के लिए तैयारी भी वैसी ही करनी चाहिए और जगह जगह पूंजीपति लोगों की जो खतौकितावत है उस पर क़ब्जा होना चाहिए । लेकिन यह नहीं हो रहा है ।

चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण की चर्चा काफी दिनों से हो रही है । मैं आसाम से आता हूं, जहां पर चाय उद्योग है । चाय उद्योग वालों के बीच गुपचुप बात हो रही है कि राष्ट्रीयकरण होने वाला है । कोई कहता है 600 एकड़ के जो चाय बागान हैं उनका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा । तब तक आप राष्ट्रीयकरण करेंगे तब तक चाय उद्योग के जो विदेशी पूंजीपति हैं वे अपनी असेट्स को यहां रखेंगे नहीं, उन असेट्स को ट्रांसफर करके ले जाएंगे । तो इस तरह से जो आप काम करते हैं कि राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण हो, उसमें आपकी बदनामी होती है। देश में आप रिएक्शनरी रिएक्शनरी चिल्लाते हैं लेकिन अपने ग़लत कामों से रिएक्शनरीज को मजबूत करते हैं । फूड टेक-ओवर के बारे में आपकी क्या व्यवस्था है । कहीं प्रस्ताव पास कर दिया, पार्लियामेन्ट में बिल ले आए, आपका बहुमत है पास कर दिया । फूड टेक-ओवर कर देते हैं लेकिन हिन्दुस्तान में तीन-चार लाख थोक व्यापारी जो काम कर रहे थे उस काम को करवाने के लिये क्या आल्टरनेटिव्ह व्यवस्था सरकार ने की । आल्टरनेटिव्ह व्यवस्था नहीं है तो सिर्फ कागज़ टेक-ओवर से काम नहीं चलेगा और अनाज का ब्लैक मार्केट होगा और देश में अनाज का भाव बढ़ेगा और लोग भूखे मरेंगे । उसी का नतीजा आप देख रहे हैं जगह जगह आज क्या होता है । महाराष्ट्र में, गुजरात में, जगह गोली चलानी पड़ती है लेकिन लाठी और गोली के जरिए आप सरकार को बचा नहीं सकते हैं । जब देश में लोगों में भुखमरी है, जैसे महाराष्ट्र में 5 रु० किलो में भी गेहूं का आटा नहीं मिलता, 10 रु० किलो में चावल नहीं मिलता, तो लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरेंगे और उस टाइम में आपका ला एण्ड आर्डर का सवाल उठ खड़ा होगा । जब पेट में भूख होती तो वायलेन्स और नान वायलेन्स की फजूल बहस में जनता नहीं

[श्री गोलाप बरबोरा]

आएगी, लोग अनाज के गोदामों को लूटेंगे । इसमें लोगों का कसूर नहीं है, इसमें सरकार और सरकार के गलत तरीकों का कसूर है ।

इसके अलावा एक्सपेंडीचर के बारे में रेस्ट्रिक्शन्स होने चाहिए । यह इस देश में सोशलिज्म की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा । आज क्या होता है ? एक्सपेंडीचर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है । देश में ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी से ब्लैक मनी ज्यादा और पूंजीपतियों को भी मालूम है, भ्रष्ट अफसरों को भी मालूम है, भ्रष्ट नेताओं को भी मालूम है कि ऐसे पैसे को वे कहीं रख नहीं पाएंगे इसलिए क्या करते हैं कि फ़जूल खर्ची में पैसा उड़ाते हैं । यहां दिल्ली में ही न्यू ईयर्स डे में खुशियां मनाने के लिए, नए साल का स्वागत मनाने के लिए बड़े बड़े होटलों में सिर्फ एक कुर्सी का रिजर्वेशन ढाई सौ, दो सौ रुपये में होता है, रात भर शराब में, मौज और मस्ती में लाखों रुपए खर्च कर देते है । उसका पैसा कहां से आता है । मुझे मालूम है, रात के अंधेरे में मिनिस्टर लोग भी पार्टियों में पहुंचते है, और व्यापारी लोग कहते हैं कि क्या करें, 10–20 हजार रुपए खर्च कर देंगे मंत्रियों और अफसरों के ऊपर तो बाद में उनसे मिल कर हमारा काम बनेगा ।

इस तरह का जो आपका तरीका है और जब तक आप खर्चे पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगायेंगे तब तक आपका सोशलिज्म बेकार है और इस तरह से आपके पास पैसा राष्ट्रीय कोष में नहीं आयेगा। भ्रष्टाचार के जरिये जो कुछ भी पैसा आता है वह फिजूलखर्ची में चौपट होता चला जा रहा है। आप को इस चीज को सुधारना है और इसके लिए ठीक व्यवस्था करनी है। सब चीजों का राष्ट्रीयकरण करने से देश का हित होने वाला नहीं है। इसके लिये आपको प्रायरिटीज मुकर्रर कर देनी चाहिये। हमारे देश में प्लानिंग कमिशन है और देश के डेवलपमेंट के लिए प्रायरिटीज का कार्यक्रम होना चाहिये। इस बारे में लोगों को आपने साथ लेना चाहिये तब जाकर हम नेशनलाइजेशन में कामयाब हो सकते हैं।

तेल के मामले में हम अभी भी विदेशी पूंजीपतियों के गुलाम बने हुए हैं और आयल रिसोर्सेज को डेवलप करने के सम्बन्ध में कोई खास काम नहीं किया गया है। अभी हमारे आयल मिनिस्टर साहब बतला रहे थे कि कहां-कहां हमारे आयल पोटैन्शियल एरियाज है। उन्होंने कैम्बे, अंकलेश्वर, गुजरात और बम्बई में आफ-शोरड्रिलिंग की बात कही है। पूर्व में आसाम की बात कही गई है, लेकिन हम यह देखते हैं कि वहा पर आयल एक्सप्लोरेशन का काम ठंप पड़ा हुआ है। वहां पर चार मिलियन टन क्रूड आयल निकला है मगर बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर जो आयल काम का है वह तीन विभागों में बंटा हुआ है और जो कुछ भी वहां पर काम होता है एक्सप्लोरेशन का वह तीन कम्पनियों द्वारा किया जाता है । इसमें आसाम आयल कम्पनी है, आयल इंडिया लिमिटेड है जिसमें 50%—50% गेयर बी० ओ० सी० और केन्द्रीय सरकार के हैं और आयल तथा नैचुरल गैस कमिशन है जो कि पब्लिक सैक्टर में है। आसाम आयल कम्पनी जो है यह पूरी तरह से ब्रिटिश ओन्ड कंपनी है। आसाम में काफी तेल है और उसको निकाला भी जा सकता है। आफ शेयर अंग्रेजी कम्पनी के हैं और इसकी वजह से वहां पर कुछ कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। जो हमारे 50 प्रतिशत सरकारी आफिसर हैं उन्हें ब्रिटिश वाले खरीद लेते हैं और यही कारण है कि हम अभी तक तेल के बारे में स्वावलम्बी नहीं बन सके हैं। इसलिए हम को इस चीज के बारे में सोचना चाहिये और सेन्टर में इस चीज को करने के लिए एक अलग से विभाग होना चाहिये जो सब चीजों को कोआर्डिनेट कर सके क्योंकि हमारे देश में पावर, बिजली और आयल की बहुत कमी है। हमारे देश में फर्टीलाइजर की भी कमी है और इन सब चीजों को हमें बढ़ाना है । जिस तरह से जापान और ब्रिटेन में मिनिस्ट्री आफ पावर है उसी तरह से हमारे यहां भी अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिये। यहां पर तो आपस में टकराव है और इस तरह से हमारा कार्य आगे नहीं बढ़ता है। आज आवश्यकता

इस बात की है कि देश में और खास कर के आसाम में जहां पर तेल उपलब्ध है वहां पर एक्सप्लोरेशन किया जाना चाहिये। इसके लिए अलग अलग एजेन्सियां नहीं होनी चाहिये बल्कि आयल एण्ड नैचुरल गैस कमिशन को यह कार्य सौंप देना चाहिये। इसके साथ ही साथ जो आसाम आयल कम्पनी है उसको सरकार को अपने हाथ ले लेना चाहिये। आयल इंडिया लिमिटेड और बी० ओ० सी०, इन दो कम्पनियों के जो पचास पचास परसेंट शेयर हैं, उनको मिलाकर एक व्यवस्था कर देनी चाहिये।

सरकार ने लैंड डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में कहा है, लेकिन वह कागज में ही फैसला होकर रह गया है। इसके लिए सरकार ने बाद में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। कई राज्यों में तो सीलिंग ऐक्ट भी हो गये हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज तक कितने लोगों को फालतू जमीन दी गई है? मैं आसाम का रहने वाला हूं और वहां की प्रान्तीय सरकार ने जो अपने को समाजवादी सरकार कहती है, उसने 50 बीघे का सीलिंग लगाया है। इसके पहले उसने 75 बीघा रखा था और इसके पहिले भी 150 बीघा की सीमा रखी थी। इस तरह से उसने 150, 75, और 50 बीघा जमीन की सीमा रखी थी इतनी बीघा की सीमा रखने के बाद कितनी जमीन उसके पास आई और उसने किसानों को बांटी? आज हम कई प्रान्तों में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि वहां पर सीमा लगाने के बाद भी कोई फालतू जमीन नहीं बची है जो लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है उनको बांटी जा सके। कांग्रेस ने तो सो-कालड प्रोग्रेसिव्ह इमेज को कायम रखने के लिए इस तरह का नारा दिया था और केवल कागजों में, रिकार्ड में सीलिंग कर दी गई। उसने तो यह चीज केवल अपने प्रचार के लिये की थी ताकि उसका नाम हो जाय, लेकिन हालत यह है कि इस चीज के ऐलान के बाद जिनके पास फालतू जमीन भी थी वह उन्होंने अपने रिश्तेदारों में बांट दी और इस तरह से जमीन के कागजात तैयार हो गये।

इसलिए जमीन का बंटवारा करना है तो पहले कांग्रेसियों को मैं बोलना चाहता हूं कि अपने दिल से पूछिये कि क्या आपमें वेस्टेट लेन्डेड इन्टरेस्ट्स हैं या नहीं। आप अपने को लेन्डेड वेस्टेड इन्टरेस्ट से मुक्त करके इस व्यवस्था का फैसला करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हमको मालूम है कि वेस्टेड इन्टरेस्ट, लेन्डेड एरिस्टोक्रेट्स कांग्रेसियों के बीच में हैं और गांवों में जिनके पास ज्यादा जमीन है, वोट के मामले में उनका प्रभाव रहता है। लैन्ड होल्डर्स लाबी के सामने सरकार को झुकना पड़ता है, चाहे आप बाहर कितना ही लैंड सीलिंग की बात करें और गरीबों में जमीन बांटने का स्लोगन दें। जमीन का बंटवारा जल्दी से जल्दी करना चाहिए नहीं तो गांवों में जो अकाल और भुखमरी की तस्वीर है उसको आप कभी साफ नहीं कर पाएंगे।

पोलिटिकल पेंशन्स का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। बहुत हल्ला हुआ दिल्ली में लोगों को लाकर ताम्रपत्र दिया गया। काफी लोग हमारे यहां भी हैं लेकिन उनकी दरख्वास्त पड़ी हुई है कहीं शिलांग में या कहीं दिल्ली में होम मिनिस्ट्री की फाइल्स में। ऐसा भी है कि कोई आज का कांग्रेसी है, आजादी के आन्दोलन में नहीं था, 42 के पहले कांग्रेस में नहीं था, कांग्रेस के आन्दोलन का विरोध भी करता था ऐसे भी लोगों को पेंशन मिली है, लेकिन आजादी के आन्दोलन में जिन लोगों ने बहुत कुछ कुर्बानी की, आज सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वे लोग कांग्रेस में नहीं हों उनके मामले का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। आसाम में हमारे ही दल में ऐसे साथी हैं, बूढ़े हो चुके हैं, कुछ कर नहीं पाते, आजादी के आन्दोलन में उन्होंने अपना सब कुछ खोया उनका मकान ब्रिटिश पुलिस ने तोड़ा, बीमार हुए, आज इधर-उधर मारे मारे फिरते है। ऐसे कई केसेज हैं। आसाम सरकार के पास जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी एप्लीकेशन दिल्ली भेज दी है और यहां पूछते हैं तो मालूम होता है कि पहुंची नहीं। यह तरीका है। देश की आजादी के लिए जो लोग लड़े, जिन्होंने कुर्बानियां दीं अगर उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो निष्पक्ष होकर

(श्री गोलप बरबोरा)

रिकार्ड देखिए और जिन लोगों का त्याग-बलिदान रहा है, उनके लिए जो कुछ हो सके दीजिए। वैसा आदमी किसी भी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, कम्युनिस्ट में हो, नक्सलाइट में हो उसकी तरफ मत देखिए।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं एप्रोप्रिएशन बिल का विरोध करता हूं। सबसे पहला कारण मेरे विरोध का यह है कि हिन्दुस्तान में इन 25 वर्षों में जो भी शांतिपूर्ण आन्दोलन चले हैं उनका कोई भी असर सरकार के ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन अगर वही आन्दोलन हिंसा का रूप धारण कर लेता है तो सरकार के ऊपर उसका असर होता है। यही कारण है कि इन दिनों जितने भी आन्दोलन शुरू होते हैं वे हिंसा के जरिए ही शुरू होते हैं और सरकार का ध्यान जाता है और सरकार कुछ करती है। अभी हाल की एक घटना है। एक शांतिपूर्ण आन्दोलन हमारी पार्टी के श्री सूर्य नारायण सिंह चला रहे थे, उन्होंने अनशन किया बिहार के मजदूर क्षेत्र में, लेकिन इन्दिरा गांधी की कांग्रेसी सरकार के नुमाइन्दे केदार पांडे के शासन में सूर्य नारायण सिंह को लाठी से इतनी मार पड़ी कि बेचारा मर गया। जलाने के टाइम में जब उसकी देह को खोला गया तो समूची पीठ का चमड़ा लाठी की मार से फट गया था। यह हालत हुई उस सूर्य नारायण सिंह की जिसने 1942 के आन्दोलन के सिलसिले में जयप्रकाश नारायण, डा० लोहिया आदि को हजारी बाग जेल से निकाल कर नेपाल पहुंचाया था और फिर नेपाल से इन लोगों को लेकर भागा था। वह सूर्य नारायण सिंह था, वह बिहार का शेर था, उसकी हालत इस सरकार के जरिए से यह हुई है। इतना ही नहीं वह बिहार का एक एम० एल० ए० भी था और उसकी यह हालत हुई है। ऐसी हालत में अगर लोग अहिंसा को छोड़कर हिंसा का मार्ग पकड़ते हैं तो कौन सी बेजा बात करते हैं। आज इस तरह की परिस्थिति सारे देश में इस सरकार ने ला दी है। सबसे विशेष बात तो यह है कि जब सूर्य नारायण सिंह को पुलिस लाठी से मार लगा रही थी उस समय पूंजीपति के घर पर बिहार का चीफ मिनिस्टर और एक यूनियन का नेता बैठ कर चाय पी रहे थे और कहा जाता है कि इन लोगों की कांसिपिरेसी की वजह से ही उनको मार लगी जिससे उनकी मौत हुई थी। हमने इस तरह का एक लैटर भी प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया।

श्री महावीर त्यागी : आपका भी यही हाल होगा।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल : हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है।

एक दूसरी बात की ओर भी आपका ध्यान खींचता हूं। अभी हम लोगों ने एक मीटिंग भागलपुर में की थी उस सिलसिले में मैं वहां गया था, राजनारायण भी वहां गये थे। उन्होंने हमें एक बात कही कि इसको पालियामेंट की प्रोसिडिंग में लाइये। उन्होंने कहा कि अभी हाल में जो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज अलग किये गये हैं उनमें एक जज जिसका नाम हेगडे है, उस जज ने हमारा मुकदमा जो अभी भी चल रहा है इलेक्शन का, वह दो बार सुप्रीम कोर्ट में गया है और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसका फैसला हुआ है, जिसमें हेगडे भी शामिल थे और हमको पूरा शक है कि इस वजह से उसको हटाया गया है और जो आज हेगडे का स्टेटमेंट निकला है वह स्टेटमेंट भी इस बात का कंफरमेशन करता है, उन्होंने साफ बात को कहा है कि हम विक्टिमाइजेशन के अन्दर पड़ गये हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के विक्टिमाइजेशन के अन्दर पड़ गये हैं; क्योंकि एक इलैक्शन केस के जरिये हम उनको खुश नहीं कर सके और इसलिये हम पर रोष है। इसलिए जो कांसिपिरेसी है वह कुमारमंगलम, गोखले और प्राइम मिनिस्टर ये तीनों मिलकर बहुत पहले से ही कांसिपिरेसी कर रहे थे हमको हटाने की। और दो जजों को क्यों हटाया है, हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज जिसके बारे में उनको डर था कि यह हमारी बात नहीं मानेगा, ऐसे जज को सुपरसीड किया गया है और इन लोगों ने इनके लिए रास्ता साफ कर दिया है, इस्तीफा देकर।

SHRI K. R. GANESH : On a point of order. While the hon. Member has every j right to put across his point of view on this i very debate that is going on in the country I today, about the supersession of the Supreme Court Judges—the other House is discussing it now and this House also will discuss it—he has brought in the Prime Minister and tried to give an angle to it saying that the supersession is due to the fact that Justice Hegde had given a verdict in the Prime Minister's case. It is my duty here to deny the statement and if anything the press statement given by the hon. Judge has definitely revealed the whole controversy that is there. I do not wish to go into that because the House will have an opportunity to discuss it.

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल : सर, प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है, उसी बात के ऊपर।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : You can go to the next point.

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल : हमने भी इसके बारे में कहा है चूंकि हमको जो एफेक्टेड आदमी है राजनारायण उसने हमको यह बात कही कि पार्लियामेंट में इसका जिक्र करने के लिए, इसलिए हमने कहा है ।

आज जो रवैया इस देश में चल रहा है, इस देश ने जो स्वतंत्रता हासिल की है वह स्वतंत्रता इस देश में रह सकेगी या नहीं यह सारे देश में चिन्ता का विषय बन गया है। जिस ढंग से इंदिरा गांधी समाजवाद का नारा देकर देश में काम कर रही है, उस काम से सारे लोगों के दिमाग में आज यह बात आ रही है कि धीरे-धीरे वह कानून के जरिये और दूसरे जरिये से ऐसी परिस्थिति बना रही है कि देश का जो जनतंत्र है, वह खत्म हो और इनकी तानाशाही कायम हो, इस तरह की परिस्थिति बना रही हैं।

डा० लोहिया ने जो पालिसी स्टेटमेंट सोशलिस्ट पार्टी का लिखा था हैदराबाद में, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश का जनतंत्र खत्म होता तो उसके पहले जो देश की शासक पार्टी रहती है, उसके अन्दर में जब जनतंत्र खत्म हो जाता है, तो उसके बाद देश का भी जनतंत्र खत्म हो जायेगा। आज कांग्रेस पार्टी की वही हालत हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर के मुह के ऊपर जवाब दे सके। शायद हमारे बोलने की रिपोर्टिंग उनके यहां न पहुंच जाये इस डर से सब कोई डरा रहता है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी के अन्दर में भी उनकी डिक्टेटरशिप हो गई है। लोगों के ऊपर भी उनकी डिक्टेटरशिप हो गई है। उस डिक्टेटरशिप को मजबूत करने के लिए जो पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ उसमें भी उन्होंने जिनको टिकट दिये उनमें अधिकांश अपनी जाति के लोगों को दिये। कांग्रेस के जो 383 आदमी जीत कर आये हैं, उनमें 180 आदमी से बेशी सिर्फ एक जाति के हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर की जाति है। इस ढंग से प्राइम मिनिस्टर चल रही है और उसका एक ही नतीजा निकल सकता है कि इस देश का जनतंत्र खत्म हो जाये और यहां तानाशाही कायम हो जाये, ब्राह्मणशाही कायम हो जाये। इस तरह की परिस्थितियां हिन्दुस्तान में कायम हो रही हैं। चूंकि हम लोग हजारों वर्ष से इस ब्राह्मणशाही के सताये हुये हैं, इसलिए हम लोगों के ऊपर उसका जो असर पड़ता है उस असर के चलते हम लोगों को यह बात बोलनी पड़ती है। और इसी लिए मैंने इस बात को आप के सामने रखा।

इसके बाद जिस ढंग से देश की बागडोर अपने हाथ में ले कर कांग्रेस सरकार ने शुरू से इन्तजाम किया है और इन्दिरा की सरकार जिस ढंग से देश का इन्तजाम कर रही है, उसका यह नतीजा हो रहा है कि आज हर चीज का अभाव है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। पीने के पानी का अभाव है। अन्न का अभाव है। बिजली का अभाव है, सीमेंट का अभाव है, फर्टिलाइजर का अभाव है । ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी जरूरत लोगों को हो और उनका अभाव न हो । हर चीज का आज देश में अभाव ही अभाव है ।

[श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल]

कहते हैं कि इस देश में प्लान चल रहा है और वह 1950-51 से चल रहा है। अभी तक जो प्लान चला है उसका नतीजा यह नहीं निकला है कि इस देश का आदमी पेट भर अन्न खा सके। बल्कि पहले जितना अन्न लोगों को मिलता था उससे प्रति व्यक्ति अन्न का औसत भी कम है और कपड़े का औसत भी कम है। यह स्थिति आज हिन्दुस्तान में इंदिरा गांधी की सरकार ने ला दी है। इस बदइन्तजामी की वजह से जिस प्रकार आर्थिक कष्ट में यहां के लोग हैं उससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन है और उस फ्रस्ट्रेशन से लोगों में चिड़चिड़ापन है और उस चिड़चिड़ेपन के कारण देश में कहीं कहीं उपद्रव शुरू होता है। उस उपद्रव को भी सरकार की ओर से जबरदस्ती दबाने की कोशिश की जाती है। अभी हाल में ला एंड आर्डर का क्वेश्चन हर जगह उठा है। यह भी आप को मालूम है कि इस सम्बन्ध में किस बेरहमी के साथ लोगों को गोली से भूना जाता है। यह सब हम लोग अपनी आंख से देख रहे हैं। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए आज सिवाये बन्दूक के दूसरा कोई यंत्र इनके हाथ में नहीं है। इसलिए ये उस तानाशाही पर उतर चुके है, जिसमें हिंसा का उपयोग करना इनके लिए अनिवार्य हो गया है। हर तरह से आज ये विफल हो चुके हैं। यह विफलता और पावर का लालच दोनों ने मिल कर आज देश में इस तरह की परिस्थिति पैदा कर दी है। इसलिए मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि जब से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उसके बाद से जिस ढंग से धीरे-धीरे बीच-बीच में आकर्षक नारे देते हुये जो बदइन्तजामी इसने की है उसके चलते यह सारी गड़बड़ी शुरू हुई है। समाजवाद यह कायम करना चाहती हैं, ऐसा उनका नारा है, लेकिन ऐसा नारा देने वालों की संसार में कमी नहीं है। हिटलर ने भी इसी तरह का नारा दिया था। वह भी अपने देश में नेशनल सोशलिज्म कायम कर रहा था, लेकिन उसी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के अंदर उसने वहां डिक्टेटरशिप कायम कर ली और आज हिन्दुस्तान में भी उसी तरह से इन्दिरा गांधी अपने नेतृत्व में सरकार लाकर अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर रही हैं। लेकिन हिटलर तो ऐसा आदमी था कि जो अपना आर्थिक प्रबंध भी कर सकता था, इंदिरा जी तो वह भी नहीं कर सकी हैं और इसके लिए अगर कोई आदमी बोलता है तो उसको गोली से दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो कार्यवाही इस सदन में हो रही है, उसका असर देश में तभी अच्छा हो सकता है कि जब प्रधान मंत्री जी के ऊपर कोई लगाम लगायी जाये जिसके चलते उन पर कोई कंट्रोल हो। यह कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम है देश की जनता। उसी जनता ने देश का सबसे बड़ा कानून--संविधान बनाया है और उस संविधान की उन्होंने जिस ढंग से मरम्मत की है वह तानाशाही है। वह कानूनी मरम्मत नहीं है, वह कानूनी अमेंडमेंट नहीं है, उसमें भी तानाशाही है और उस तानाशाही के जरिये वे शासन चला रही हैं। यह कहना बहुत आसान है कि हम संविधान के अंदर कानून बनाते हैं और मेजारिटी हमारे पास है, इसलिए जो हम करते हैं वह ठीक है। लेकिन मेजारिटी रहने पर भी जिस ढंग से देश के सबसे बड़े कानून को उन्होंने मरम्मत की है उसमें मेजारिटी और माइनारिटी कोई बात नहीं रह गयी है। उस मेजारिटी के ऊपर पाबंदी रखने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स रहते है, वह मेजारिटी पर भी लगाम लगाये रहते हैं। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने संविधान की मरम्मत की है और उसे मरम्मत करने का अधिकार अपने बहुमत के जरिये से ले लिया है, उसका नतीजा यह है कि आज संविधान की पाबंदी उनके सामने कोई चीज नहीं रह गई है और एक तरह से उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप यहां कायम कर ली है।

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I want to invite the attention of the Government to the problem of unemployment of educated Scheduled Castes and Scheduled

Tribes. It is true that the Government has provided reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. There is 50 per cent reservation for the Scheduled Castes and 7-1/2 per cent, for the Scheduled Tribes. It is also true that this right to reservation flows from the provision of the Constitution itself. I have been collecting data as to the total recruitment in the year 1971-72. My enquiry shows that even in respect of the two years the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have not been adequately represented in the services. I will give you only one example under the Ministry of Finance.

The Life Insurance Corporation has also given a statement about the employment positioa of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. So far as the class I officers are concerned, there are more than 3,000 class I officers.

Out of them, there are only three Scheduled Castes and two Scheduled Tribes. That means that there is not even one as against one thousand. So this is the state of affairs. The reservation is not there only in Government services, it has also been extended to the public sector undertakings. But these figures show that though there is provision, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are virtually shut out from making entry into the services. That appears to be the state of affairs.

Secondly, the Government has no doubt set up a machinery to ensure that the candidates from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are provided adequate opportunity in the matter of employment. But our experience is that these instructions and these administrative directives are not followed at all. Nobody bothers about them. Nobody takes all these instructions seriously, with the result that when a query is made as to why, in spite of the fact that there is provision for reservation and there are so many posts, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are not appointed, the stereotyped reply that comes is, "suitable candidates are not available". I would submit. Sir, that the Government has really done good work in providing some benefits to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the form of scholarships. During the last ten years, there has been a great increase in the number of graduates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all the faculties—arts, commerce, science, technology, medicine and engineering. But unfortunately those who are graduates and double-graduates are knocking from door to door, going here and there making applications for jobs. And they are required to wait for years to get employment. On the other hand, we are told that suitable candidates are not available. So. the situation which is now presented before us shows that there is something wrong and sometimes I cany the impression that it is more or less a class prejudice that comes in the way. Everybody and all political parties speak with vehemence that this should be done for the Scheduled Castes, that this should be done for the Scheduled Tribes. But when it comes to doing something practical, doing real good to them, we find that the real work is not done.

My suggestions are very few. In the first place, we want that these rights which flow from the Constitution should be given statutory recognition. Unless there is legislation providing reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it will not be possible for an aggrieved person to assert that right. Let there be a forum. If my legitimate right to be appointed to a reserved post is denied to me, I can approach that forum with my grievance. But since the reservation now is there only through the channel of Government instructions and executive directions, we have no statutory right as such. So, my first suggestion is that the time has now come when there should be statutory law providing for reservations so that if that right is denied to me, I can assert my right through a forum that will provide me the right. The second suggestion is that Scheduled Caste and Scheduled Tribe associations should be recognised so that if a legitimate right is denied to them, then

[Shri N. H. Kumbhare.j that association can agitate and secure that right which is due to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

And then my third suggestion is that there is a dangerous trend in the sense that general unions in public sector have passed resolutions that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should not be provided reservation in promotions. My submission is that the unions have no right to take away what is given to us under the Constitution. This is a very important right which flows from the Constitution itself. Therefore, the unions should not be allowed to do anything by which our right will be taken away. And this is also a trend of which the Government should take a serious note.

That is all I wanted to say. Thank you.

SHRI K. R. GANESH : Mr. Vice-Chairman, I have heard with very great interest all the speeches that the honourable Members have made. The debate has covered a very large area as normally happens in a debate on an Appropriation Bill. The whole national scene as well as policies of the Government, the extent of the economic crisis, the question of food-grains take-over, education, defence, even the question of our foreign relations, our Prime Minister's visit to Ceylon, and, of course, the very live controversy as regards the supersession of the Supreme Court Judges, etc. have been covered by the honourable Members. The House also had occasion to debate, have a general discussion, on the Budget and quite a lot of points had also been raised there. I would like to submit two or three important aspects of the whole matter. This country is in the process of development, is in the process of transition...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Mr. Ganesh, if you like, you can continue tomorrow.

SHRI K. R. GANESH : All right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at fifty-four minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 3rd May, 1973.

MG1PRRND—II—12RSS/73—20-7-73—570.